प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ... सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

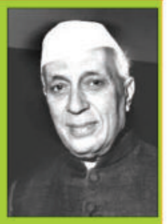

अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं।
जवाहरलाल नेहरू

वर्ष-08, अंक - 24 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 26 मार्च 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

धर्म बदला तो एस.सी. का आरक्षण खत्म

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण और अनुसूचित जाति के दर्जे को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। जिसमें धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति (एससी/ एसटी) का दर्जा और उससे मिलने वाली सुरक्षा/आरक्षण का लाभ समाप्त हो जाते हैं। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि, हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म जैसे ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति/ जनजाति का स्टेटस नहीं मिलेगा।

इस फैसले के बाद जो व्यक्ति इन जातियों से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन या मुस्लिम बने हैं वे अब एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट का लाभ भी नहीं ले सकेंगे।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि, कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म छोड़कर अन्य धर्म ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाता है तो वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह जाएगा। कोर्ट ने कहा कि, यह वैधानिक रोक पूर्ण है और इसमें किसी अपवाद की गुंजाइश नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें एक पादरी द्वारा (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कराई एफआईआर को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के क्लॉज-3 के तहत धर्मांतरण के साथ ही एससी का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि, एससी/ एसटी एक्ट के तहत शिकायत केवल वही व्यक्ति दर्ज करा सकता है जो वास्तव में इस समुदाय से संबंधित हो। धर्म छोड़ने के बाद यह वैधानिक अधिकार खत्म हो जाता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, दोहरी पहचान संभव नहीं है सामान्य धाराओं में ही दर्ज होगा केस

कोर्ट ने कहा है कि, 1950 के आदेश में स्पष्ट है कि, हिंदू, सिख या बौद्ध ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं अन्य धर्म अपनाने पर जन्म के आधार पर मिलने वाला यह दर्जा प्रभावी नहीं रहता है। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि, कोई व्यक्ति एक साथ ईसाई धर्म की रीतियों का पालन करें और एससी होने का संवैधानिक लाभ ले।

कोर्ट ने कहा है कि, जो व्यक्ति एससी की श्रेणी में नहीं आता है वह एससी/ एसटी एक्ट का लाभ नहीं ले सकता। ऐसे मामलों में सामान्य धाराओं के ही केस दर्ज करना होगा।

एमपी अजब है अधिकारी मस्त, जनप्रतिनिधि पस्त

शासन और प्रशासन लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ है। शासन का कार्य है योजना बनाना और प्रशासन का कार्य है उन योजनाओं का मूर्त रूप देना। सामान्यतः दोनों के समन्वय से ही सभी कार्य पूर्ण होते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में प्रशासन के आगे शासन की चमक कुछ फीकी सी पड़ गई है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी नौकरशाही हावी होने के आरोप लगते रहते थे। लेकिन वर्तमान में मोहन यादव की सरकार में नौकरशाही कुछ ज्यादा ही हावी हो चुकी है जिसके एक नहीं कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। लगभग 5-7 विधायकों को अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देना इस बात का सबूत है कि, पार्टी में सब कुछ ठीक दिखाने का दावा भले किया जा रहा हो लेकिन यह सही नहीं है। कैबिनेट बैठकों में भी वरिष्ठ मंत्रियों की अनुपस्थिति, कई विधायको द्वारा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और अपनी ही सरकार की सार्वजनिक आलोचना यह दर्शाता है कि, अनुशासित पार्टी का दावा करने वाली पार्टी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और सरकार के जन प्रतिनिधियों की एक ही पीड़ा है कि, अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं और उनकी अनुशंसा वाले कार्यों की अनदेखी की जाती है।

हाल ही में रतलाम जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके पति को कलेक्टर ने मिलने का समय तक नहीं दिया मजबूरन अध्यक्ष पति व अध्यक्ष ने वहीं धरना प्रारंभ कर दिया। जो बाद में समझाईस के बाद खत्म किया गया। यह समस्या केवल रतलाम की नहीं है पूरे प्रदेश में लगभग ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। जहां अधिकारी वर्ग हठधर्मिता के चलते जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कर रहे हैं जिससे जनप्रतिनिधियों के मन में विरोध की चिंगारी भड़क रही है। हालांकि फिलहाल वे पार्टी अनुशासन के चलते कुछ भी बोलने से डर रहे हैं लेकिन नौकरशाही के हावी होने के परिणाम अंततः सरकार को ही भुगतना पड़ सकते हैं।

फोटो24- रतलाम जिला प.अ. व उनके पति कलेक्टर के नही मिलने पर कलेक्टर कार्यालय में बेठे धरने पर।

ईंधन संकट की अफवाहः देशभर में अफरा-तफरी, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें

नई दिल्ली।

देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैली अफवाहों ने आम लोगों में घबराहट पैदा कर दी है। नोएडा, हैदराबाद, नागपुर सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिलीं। लोग डिब्बों और बोतलों में भी ईंधन भरवाने के लिए उमड़ पड़े, जिससे कई स्थानों पर अस्थायी रूप से भंडार समाप्त होने की स्थिति बन गई।

कई जगहों पर हालात ऐसे हो गए कि पंपों पर 'ईंधन उपलब्ध नहीं' के बोर्ड लगाने पड़े। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह वास्तविक कमी नहीं, बल्कि अचानक बढ़ी मांग का परिणाम है। अधिकारियों के अनुसार देश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, देवास, मंदसौर, बुरहानपुर और झाबुआ में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले। उज्जैन में तो मंगलवार रात से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, जिसके चलते कई पंपों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और स्थिति संभालने के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा।पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि यह अफवाह फैली है कि जल्द ही पंप बंद हो सकते हैं, जिसके कारण लोग घबराहट में आवश्यकता से अधिक ईंधन खरीद रहे हैं। हैदराबाद और नागपुर में भी आपूर्ति सामान्य रहने के बावजूद लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है।

इसी बीच रसोई गैस को लेकर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अयोध्या, आगरा, उदयपुर और वडोदरा सहित कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई लोग गैस सिलेंडर पाने के लिए घंटों, बल्कि रातभर इंतजार कर रहे हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर मध्य-पूर्व में तनाव के बावजूद भारत में ईंधन और रसोई गैस की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक खरीदारी से बचें, ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

अदालत का अहम फैसला, सीबीआई को बैंक खाते खोलने के निर्देश

नई दिल्ली।

राउज एवेन्यू स्थित जिला अदालत ने साइबर धोखाधड़ी मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को याचिकाकर्ता के बंद किए गए बैंक खातों को पुनः चालू करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई के लिए उसका अपराध से सीधा संबंध होना आवश्यक है, जिसे जांच एजेंसी स्थापित नहीं कर पाई।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 106, पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के समान है, जो केवल संपत्ति की जब्ती से संबंधित है। वहीं अपराध से अर्जित आय को संलग्न करने के लिए धारा 107 के अंतर्गत न्यायिक निगरानी आवश्यक होती है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सीबीआई यह साबित नहीं कर सकी कि संबंधित बैंक खातों में जमा राशि सीधे तौर पर अपराध से जुड़ी है। साथ ही ठगी की कुल राशि का सही आकलन भी नहीं किया गया।

प्रक्रियागत त्रुटियों पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि बैंक खातों को बंद करने की सूचना मजिस्ट्रेट को देने में लगभग 10 दिन की देरी हुई, जो लापरवाही दर्शाती है। हालांकि केवल देरी के आधार पर कार्रवाई को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने खातों को पुनः चालू करने का आदेश देते हुए यह शर्त रखी कि याचिकाकर्ता को खातों में मौजूद राशि के बराबर का निजी मुचलका जमा करना होगा।

उत्तराखंड के बाद गुजरात में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित

अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत समान नागरिक संहिता विधेयक को लंबी चर्चा के बाद बहुमत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही गुजरात, उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां यह व्यापक प्रभाव वाला कानून पारित हुआ है। यह विधेयक मंगलवार दोपहर 3 बजे विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद लगभग साढ़े सात घंटे तक इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे तर्क-वितर्क भी देखने को मिले। अंततः रात 10 बजकर 37 मिनट पर इसे बहुमत से पारित घोषित किया गया। मतदान के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधेयक पर विस्तृत उत्तर देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के मामले में गुजरात का दूसरा राज्य बनना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह कानून जाति और धर्म से ऊपर उठकर समाज को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी नागरिकों की धार्मिक आस्थाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इस कानून में महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में समान भागीदारी देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि विवाह पंजीकरण से जुड़े वर्तमान प्रावधान जारी रहेंगे और अपनी पहचान छिपाकर विवाह करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और कोई नागरिक नीचे नहीं है। उन्होंने समान और सशक्त गुजरात का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना की।

लिएंडर पेस ने नितिन नबीन से की मुलाकात, भाजपा में शामिल के संकेत

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में भाजपा को जल्द ही एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी का साथ मिल सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की है। पेस करीब पांच वर्ष पहले राज्य में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे।

मंगलवार शाम कोलकाता में पेस और नबीन के बीच बैठक हुई। जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी उपस्थित रहे। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच चर्चा हुई है और संभावना जताई जा रही है कि पेस शीघ्र ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में गोवा में पेस ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया था। हालांकि पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई और वे गोवा प्रदेश समिति के सदस्य भी नहीं बने थे। जनवरी 2022 में घोषित समिति में 69 सदस्य शामिल थे। मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक अर्घ्य रॉय प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके साथ ही ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन से जुड़े तथा ग्रेटर कूच बिहार आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक राजबंशी नेता बंशीबदन बर्मन ने भी पार्टी के राज्य मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। नितिन नबीन ने पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई से प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए सूक्ष्म स्तर पर योजना बनाकर जनता से संपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

मतदान का अधिकार छीना जा रहा, आगे नागरिकता पर भी खतरा - ममता बनर्जी

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला करते हुए संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने उत्तर बंगाल के मैनागुड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार छीना जा रहा है।

उन्होंने आशंका जताई कि केंद्र सरकार का अगला कदम राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू कर नागरिकता पर प्रभाव डालना हो सकता है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से कुछ समुदायों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजबंशी समुदाय के नाम सूची से हटाए गए हैं और कई स्थानों पर महिलाओं के नाम भी हटाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इस प्रक्रिया के कारण किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार और भाजपा संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं और मतदान के अधिकार को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिना नामलिए उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पर भी निशाना साधते हुए लोगों से उन्हें हटाने का आह्वान किया।

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत जनता है और वही उनके साथ खड़ी है। उन्होंने भाजपा और निर्वाचन आयोग पर मिलीभगत से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया है, अब उनके पास केवल जनता का समर्थन ही बचा है।

उन्होंने कोलकाता हवाई अड्डे पर भी निर्वाचन आयोग के एक पुराने दस्तावेज का हवाला देते हुए इसी तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि छिपकर काम करने के बजाय खुलकर सामने आकर मुकाबला करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने साथ अधिवक्ता ले जाने की सलाह दी है।

कांग्रेस को नोटिसः 24 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड के कार्यालय खाली करे

नई दिल्ली।

देश की राजनीति के सबसे ऐतिहासिक पतों में शामिल 24 अकबर रोड अब कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल सकता है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस को दिल्ली स्थित अपने दो प्रमुख कार्यालय 24 अकबर रोड और 5 रायसीना रोडकृखाली करने के लिए बेदखली का नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार पार्टी को ये दोनों संपत्तियां 28 मार्च तक खाली करनी होंगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नोटिस कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुए हैं, जिससे पार्टी के पास कानूनी और राजनीतिक विकल्पों पर विचार करने के लिए सीमित समय बचा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और इन्हें खाली करने की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। इससे कांग्रेस के भीतर चिंता बढ़ गई है कि क्या वह इन दोनों राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संपत्तियों पर अपना अधिकार बनाए रख पाएगी। पार्टी अब अपने अगले कदमों पर विचार कर रही है, जिसमें न्यायालय का रुख करना और सरकार से अतिरिक्त समय मांगना शामिल है।

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संपत्ति के आवंटन को पुनः व्यवस्थित करने के लिए कुछ और समय का अनुरोध कर सकती है। विचाराधीन विकल्पों में यह भी शामिल है कि किसी वरिष्ठ नेता को राज्यसभा में भेजकर उनके नाम पर आवास आवंटित कराया जाए, ताकि उसका उपयोग जारी रखा जा सके। हालांकि इसके लिए 28 मार्च की समय-सीमा से पहले तेजी से राजनीतिक और कानूनी प्रयास करने होंगे।

लंबे समय से कांग्रेस नेतृत्व से जुड़े 24 अकबर रोड के संभावित रूप से हाथ से निकल जाने के प्रतीकात्मक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। 5 रायसीना रोड के साथ ये दोनों स्थान दिल्ली में पार्टी के समन्वय और निर्णय लेने के प्रमुख केंद्र रहे हैं।

पचास हजार का काम, पंचायत ने आहरण कर लिए लाखों रुपए

मौके से बिल अनुसार सामग्री गायब, पूर्व सांसद प्रतिनिधि ने बिल की प्रति के साथ की शिकायत

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

पिछले 6 माह में लगातार चर्चा में रही पेटलावद विकास खंड की ग्राम पंचायत तारखेड़ी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार ग्राम पंचायत पर निर्माण कार्य में बड़े भ्रष्टाचार के साथ गंभीर आरोप लगे है। नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण के चल रहे कार्य को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे है। पूर्व सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह राठौर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद को लिखित शिकायत दर्ज करवाते हुए ग्राम पंचायत पर निर्माण कार्य के नाम पर हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। शिकायत में बताया गया कि, ग्राम पंचायत भवन जिसकी लागत लगभग 25 लाख रुपए है उसका काम ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है, मौके पर बमुश्किल पचास हजार रुपए तक का निर्माण खर्च किया गया। लेकिन ग्राम पंचायत ने निर्माण के नाम पर लगभग 9 लाख के बिल लगा दिए। जो सामग्री ग्राम पंचायत ने खरीदना बताई है वो मौके पर कही नहीं दिखाई दे रही है। पूर्व सांसद प्रतिनिधि का आरोप है कि, ग्राम पंचायत ने बिना निर्माण के ही गलत तरीके से राशि आहरण कर ली जो गलत है जिसकी जांच की मांग शिकायत में की गई।

शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह राठौर ने बताया कि, उक्त मामले को एसडीएम पेटलावद को शिकायत दर्ज करा कर जांच की मांग है।

पूर्व में लग चुके है गंभीर आरोप ,सचिव हो चुका है निलंबित

ग्राम पंचायत तारखेड़ी यू तो विश्वमंगल धाम के लिए प्रसिद्ध है लेकिन इन दिनों ग्राम पंचायत के कार्यों को लेकर हो रही लगातार शिकायतों से चर्चा में है। इससे पूर्व में भी प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी शिकायत हो चुकी है जिसकी जांच के बाद सचिव को निलंबित किया जा चुका है। वहीं ग्राम पंचायत में शासन द्वारा किए जाने वाले अनाज वितरण को लेकर भी शिकायते हो चुकी है। देखा जाए तो जनपद पंचायत पेटलावद क्षेत्र की ग्राम पंचायतो में एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर आवाजें उठने लगी है।

शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग, गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक

माही की गूंज ,करवड़। अरुण भोला पाटीदार

समीपस्थ ग्राम बड़ी देहंडी में सोमवार दोपहर बिजली के शॉर्ट सर्किट ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। दोपहर के वक्त जब घर के सदस्य अपने खेतों पर काम करने गए हुए थे, तभी अचानक घर में लाइट फाल्ट होने के कारण आग लग गई। बंद घर से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद तुरंत घर के मालिक को सूचना दी गई और ग्रामीण बड़ी संख्या में मदद के लिए दौड़ पड़े। ग्रामीणों की मदद से आग बुझा कर काबू पाया गया।

भाजपा के नेता तेजमल सोलंकी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए पास ही स्थित एक मकान के बाहर बने हौज से बर्तनों में पानी भर-भरकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इसी बीच सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग को और फैलने से रोका जा सका, लेकिन तब तक घर के भीतर रखा अधिकांश सामान राख हो चुका था। हादसे की खबर मिलने पर पटवारी अनिता ताड़ भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और नुकसान का जायजा लेकर पंचनामा तैयार किया। उन्होंने बताया कि, इस अग्नि कांड में पीड़ित परिवार का भारी नुकसान हुआ है, जिसमें घर में भंडारित क्विंटलो भर सोयाबीन, गेहूं और तुवर जैसी फसलें पूरी तरह जल गई हैं। इसके अलावा घरेलू उपकरण जैसे एलईडी टीवी, पंखे, संदूक और अन्य कीमती सामान भी आग की भेंट चढ़ गए हैं। पटवारी ने आश्वस्त किया कि, तैयार किया गया पंचनामा वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाएगा ताकि प्रभावित परिवार को नियमानुसार जल्द से जल्द सरकारी सहायता मिल सके।

प्रतियोगिताः हरि सुंदरकाण्ड मंडल की टोली ने जीता प्रथम पुरस्कार

माही की गूंज, पेटलावद।

हिन्दू नववर्ष अवसर एवं स्वर्गीय मंगल भट्ट की पुण्य स्मृति में श्री बजरंग रामायण मंडल द्वारा आयोजित ÷पंचम भव्य सुंदरकाण्ड प्रतियोगिता÷ बामनिया रोड स्थित सुंदर मैरिज गार्डन में आयोजित हूई। इस भव्य आयोजन में सुंदरकाण्ड की मधुर चौपाइयों और प्रभु श्रीराम के जयघोष से सम्पूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। सायं 8 बजे आरम्भ हुआ यह आध्यात्मिक आयोजन देर रात 1:30 बजे तक निरंतर चलता रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्वालियर से पधारे सुप्रसिद्ध सुंदरकाण्ड वक्ता एवं लेखक अंकित शर्मा द्वारा गणेश वंदना एवं हनुमान चालीसा के सस्वर पाठ से हुआ।

कड़े मुकाबले में जीते पुरस्कार

प्रतियोगिता में विभिन्न नगरों और राज्यों से आए सुंदरकाण्ड मंडलों ने अपनी मधुर प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। प्रथम पुरस्कार (22,222 रूपए) स्व. मिठालालजी नंदलालजी अग्रवाल की स्मृति में श्री हरि सुंदरकाण्ड मंडल (बरमंडल), प्रतापगढ़-राजस्थान, द्वितीय पुरस्कार (15,555 रूपए) स्व. मोहनलालजी चोयल की स्मृति में श्री महाकाल म्यूजिकल ग्रुप धामनोद (निमाड़), तृतीय पुरस्कार (11,111 रूपए) स्व. डॉ. देवेन्द्र प्रसाद भट्ट की स्मृति में श्री प्रेम म्यूजिकल सुंदरकाण्ड ग्रुप सुठालिया (ब्यावरा), चतुर्थ पुरस्कार (7,777 रूपए) स्व. रघुवीरसिंह गौड़ की स्मृति में श्री लवकुश बंधु भक्ति मंडल बिजयनगर (अजमेर), पंचम पुरस्कार (6,666 रूपए) स्व. पुरुषोत्तमजी सामवेदी की स्मृति में श्री रामदास रामायण मंडल आलीराजपुर, षष्ठम् पुरस्कार (5,555 रूपए) स्व. विजयजी देवड़ा की स्मृति में श्री सनमुख सुंदरकाण्ड परिवार, सुखसर (गुजरात) को मिला। कार्यक्रम के अंत में प्रभु श्रीराम और हनुमानजी की आरती उतारी गई, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से सहभागिता की।

पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए बांटे 200 सकोरे

माही की गूंज ,पेटलावद।

भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही बेजुबान पक्षियों के दाना-पानी की व्यवस्था के लिए जैन सोशल ग्रुप संगिनी मैत्री पेटलावद ने सराहनीय पहल की है। ग्रुप द्वारा अपनी जीवदया की परंपरा को जारी रखते हुए इस वर्ष भी नगर के 200 से अधिक परिवारों को निःशुल्क सकोरे वितरित किए गए। ग्रुप की संस्थापक अध्यक्ष श्वेता कटकानी और रीना मुथा ने जानकारी देते हुए बताया कि, बढ़ते तापमान को देखते हुए पक्षियों के लिए दाना-पानी का संकट खड़ा हो जाता है। इसी उद्देश्य से हर साल की तरह इस बार भी सकोरों का वितरण किया गया है। ताकि लोग इन्हें अपने घरों की छतों और आंगन में टांग सकें। ग्रुप ने संकल्प दोहराया कि, आने वाले समय में भी जीवदया से जुड़े विभिन्न सेवा कार्य निरंतर किए जाएंगे।

इस सेवा कार्य के दौरान ग्रुप की सचिव ममता मांडोत, उपाध्यक्ष सोनाली जैन, कोषाध्यक्ष प्रति पटवा, सपना पालरेचा, अल्पना पटवा, सोनु भंडारी, मोना पटवा, भावना सोलंकी, मधु भंडारी, अमिता भंडारी, मेघा भंडारी, रचिता मूणत, सरिता पितलिया, सरिता चाणोदिया और पूजा पीपाड़ा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दिवार सडक निर्माण मे जमीदोज, ठेकेदार अबतक गायब

माही की गूंज खवासा। सुनिल सोलंकी

6 माह पहले खवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नई दिल्ली से एक टीम निरीक्षण करने आई थी। जिसमें बड़ी ही तीव्र गति से साफ-सफाई के साथ अस्पताल को चाक-चोबंद कर दिया गया था। ताकि अस्पताल की कोई कमी न दिखें। वही दिल्ली से आई टीम ने खवासा स्वास्थ्य केंद्र को भी ए ग्रेड की उपाधि दी गई। लेकिन थोड़े दिन बाद जब रतलाम-झाबुआ रोड का नए सिरे से निर्माण किया गया। तो खवासा में सीसी रोड के साथ अस्पताल की दीवार तक को तोड़ दि गई।

जानकारीनुसार खवासा में एमपीआरडीसी व ठेकेदार ने मिलकर जिस रोड को 10 मीटर तक चौड़ा करना चाहिए था। उसको 10 मीटर तक चौड़ा न करते हुए कम ही चौड़ाई ली गई। जिससे कई जगह रोड को कम चौड़ाई के कारण मोड़ भी काफी दिखाई दे रहा है। तो वही बात करें खवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तो यहां बाउंड्रीवाल को ठेकेदार ने पूरी तरह से जमीनदोज करके वहां नाली का निर्माण कर दिया गया। खवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ डॉक्टर राकेश निनामा ने बताया कि, अस्पताल के स्टाफ के साथ मरीजों को भी यहां परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तो वही रात में भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस समय इस दिवार को तोड़ी गई थी उस समय ठेकेदार आया था और मौके पर कहा था कि, हम इसको नई दिवार के साथ रिपेयर करवा कर देंगे। लेकिन अभी तक ठेकेदार ने इस बाउंड्रीवॉल को कोई भी नए सिरे से बनाने का कार्य शुरू नहीं किया है जिससे परेशानियां हो रही है। डा. निनामा ने बताया कि, हमने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ ही झाबुआ जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को भी अवगत करवा दिया लेकिन अभी तक ठेकेदार द्वारा न तो निर्माण कराया न ही विभागीय अधिकारियों ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। डॉ राकेश निनामा ने आरोप लगाया कि, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ही बाउंड्री क्यों तोड़ी गई जबकि पास में दूसरी साइट पर छात्रावास की बाउंड्री भी थी लेकिन उसको नहीं तोड़ा गया। तो वहीं रोड निर्माण में भी अनियमिता बरती गई जिससे अभी से ही उसमें दरारे आना शुरू हो गई है। एमपीआरडीसी को इस और ध्यान देकर हमारी बाउंड्रीवाल का निर्माण करवाना चाहिए।

विद्यारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ कर बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए

माही की गूंज, मेघनगर। जिले में चलाए जा रहे विद्यारंभ उत्सव कार्यक्रम को धरातल पर मजबूती प्रदाय करने हेतु मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर सुश्री अवनधती प्रधान रानू कालोनी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंची। यहां उन्होंने शिक्षकों, आम लोगों कि उपस्थिति में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर स्कूली जीवन में प्रवेश कर रहे 5-6 वर्ष के 20 बच्चों को ÷विद्यारंभ प्रमाण पत्र÷ प्रदाय किए। साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश को भी उपस्थित लोगो, अभिभावकों के साथ साझा किया और बताया कि, इस विद्यारंभ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश छोटे बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा के प्रति मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार और सुदृढ़ करना है। साथ ही उन्हें शिक्षा के प्रति जाग्रत करना और उनके आत्मविश्वास को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बच्चों का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही बच्चों को कॉपी,पेन पेंसिल सहित शिक्षा कि जरूरी सामग्री भी वितरित की और मिठाई खिलाकर बच्चों का उत्साह वर्धन किया गया। एसडीएम ने कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों,शिक्षकों के समक्ष प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

मजहबी मोर्चेबंदी का महायुद्ध और भारत में मुस्लिम मन का अंतर्द्वंद्व

माही की गूंज, झाबुआ।

पश्चिम एशिया का युद्ध मजहबी मान्यताओं से अधिक राजनीतिक हितों और शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ दिखाई देने लगा हैं। क्योंकि सभी सुन्नी देश ईरान को एक विस्तारवादी वैचारिक खतरे के रुप में देखते हैं, और वह अपने प्रभाव के विस्तार के लिए प्रयासरत है और वह विभिन्न संगठनों के जरिये अपनी पकड़ को शक्तिशाली करता है। वहीं ईरान, सुन्नी देशों को पश्चिमी शक्तियों के ऐसे प्रतिनिधियों के रुप में देखता है जो उसके प्रभाव को सीमित करने का काम करते हैं। बस यही इस संघर्ष का केन्द्रीय विरोधाभाष है।

पश्चिम एशिया का युद्ध सिर्फ ईरान बनाम इजरायल या फिर तेहरान बनाम वाशिंगटन संघर्ष के रुप में ही सिमट कर नहीं रह गया। यह टकराव अब भयंकर स्वरुप लेकर बहुस्तरिय बनता जा रहा है। इस संघर्ष में उर्जा के गंभीर संकट के साथ भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, वर्गीय पहचान, वैचारिक वैधता और रणनीतिक अवसरवाद जैसे पहलु भी जुड़ते जा रहे हैं। इसमें शिया सुन्नी टकराव की रेखाएं भी चौड़ी हो रही है। ईरान ने अपने वैचारिक प्रभाव की राह में आने वाले अवरोधों को काटने के लिए फलस्तीन संघर्ष जैसी उन मांगों के साथ जोड़ लिया जिसमें वैचारिक दरारों के लिए कोई जगह न बचे। इसके लिए ईरान ने कुछ संगठनों को पोषित भी किया। इससे ईरान के शिया संगठनों का नेटवर्क उभर गया। दोनों खेमों के बीच यह विभाजन मजहबी नहीं बल्की भू-राजनीतिक भी है।

ईरान की पूर्वी सीमा पाकिस्तान और अफगानीस्तान से सटी हुई है, सुन्नी विद्रोहियों का गढ़ होने के नाते यह चरमपंथी गतिविधियों का केन्द्र है। आईएसआईएस, खुरासान और जैश अल-अदल संगठन इसी क्षेत्र में सक्रिय हैं, ये कट्टर शिया विरोध की भूमी पर ही पनपे हैं और ईरान का विरोध करते हैं। इसके कारण ईरान की पूर्वी सीमा पर अस्थिरता पैदा की जा सकती है। जिससे सुरक्षा पर दबाव बड़ेगा और पूर्वी सीमा पर ईरान को अपने सैन्य संसाधन झौंकने पड़ेंगे, और वह दूसरे मोर्चों पर कमजोर हो सकता है। पहले भी इसका रणनीतिक लाभ अमेरिका ले चुका है, किंतु वर्तमान में स्थिति अनुकूल नहीं है। इसके विपरित वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सक्रिय आतंकियों खटास है, और उन पर नियंत्रण भी मुश्किल है, फिर एक बार उनको सक्रिय करने के बाद उन्हें निष्क्रिय करना भी मुश्किल है।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध ने पहले से जटिल स्थिति को और ज्यादा उलझा दिया है। पाकिस्तान अपनी भू-राजनीतिक स्थिति को फिर से पाना चाहता है परंतु पिछली बार जिस तरह उसने सोवियत-अफगान के बीच युद्ध में वाशिंगटन से लाभ लिया था वह इस बार अवसर नहीं पा सकेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबन शासन अब पाकिस्तान के रहमोकरम पर नहीं है। अफगानिस्तान की अपनी प्राथमिकताएं है वहां बहुत से आतंकी समूह सक्रिय है, जिनकी निष्ठाएं समय-समय पर बदलती रहती है। यह समूह ईरान युद्ध में उतरते है तब पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया के बीच की रेखाएं धुंधली होती जाएगी फिर हर मोर्चा दूसरे से जुड़ जाएगा और भौगोलिक व मजहबी दरारें उभरेगी। इस टकराव की आंच सिलसिलेवार ढ़ंग से सीरिया और खाड़ी के साथ ही पूर्वी अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक फैलेगी, जिसकी चिन्गारियां भारत तक भी आ सकती है। वहीं भारत में मुस्लिम के मन में एक अलग ही अंतर्द्वंद्व चल रहा है।

भारतीय उपमहाद्वीप का वह मुस्लिम जो गाजा या ईरान पर तीखी प्रतिक्रिया देता है वहीं मुस्लिम पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में मारे गए मुसलमानों पर चुप्पी साध लेता है। भारतीय मुसलमान बड़े ही पशोपश में है क्योंकि तथाकथित इस्लाम को किससे खतरा है उनकी स्पष्ट धारणा थी परंतु अब वे युद्ध का खुलकर समर्थन नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ईरान प्रतिक्रिया स्वरुप हवाई हमलों से पश्चिमी एशिया खाड़ी के घोषित इस्लामी देशों को भी बूरी तरह से घायल कर रहा है। यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इराक, जार्डन और सऊदी अरब में ईरान हमला कर रहा है जहां सदियों पहले पेगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ, इस्लाम ने मजहबी आकार लिया, जहां मक्का मदीना भी स्थित है। तब क्या भारतीय मुसलमानों के लिए स्थिति दुविधाजनक हो गई है। क्योंकि भारत में मुसलमानो ने उस समय विरोध प्रदर्शन किया जब ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया पर अब ईरान का विरोध नहीं कर रहे। जबकी उसने उन खाड़ी देशों में ही हमला किया जो इस्लाम को मानते हैं। और तो और कश्मीर के मुसलमान अपना जमा पैसा, गहना, धन तक ईरान को दान करने लगे है। उस ईरान को जो खाड़ी के इस्लामिक देशों पर हमला कर रहा है।

सऊदी अरब के शासक मक्का मदीना के संरक्षक मोहम्मद बिन सलमान 2017 से लगातार ईरान की नीतियों का विरोध करते रहे और 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति को इस्लामी दुनिया में बढ़ती असहिष्णुता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। जबकि सऊदी अरब भी कट्टरपंथी वहाबी सलाफी विचारधारा से प्रभावित तौहीद (एकेश्वरवाद) की कठोर व्याख्या करते हुए सुफीवाद, शिया रिति रिवाजो का विरोध करता रहा है, और इस विचारधारा के प्रभाव में विश्व के अंदर मस्जिदों, मदरसों और इस्लामी संस्थानों को वित्तपोषित करता रहा। किंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के चलते सऊदी अरब स्वयं को मध्यकालिन मानसिकता से बाहर निकलकर व्यवहारिक, उदार और सह अस्तित्व आधारित समाज बनाना चाहता है। उनका कहना है कि हम अपनी जिंदगी के अगले 30 वर्ष विनाशकारी विचार से झुझने में नहीं बिताएंगे। इसी के कारण सऊदी अरब में बीते एक दशक से सामाजिक सुधार निरंतरता पर है जो विशुद्ध इस्लामिक दृष्टीकोण से वर्जित है।

रिंकेश बैरागी

तब क्या यह कारण हो सकता है कि भारतीय मुसलमान सऊदी अरब, युएई, या अन्य खाड़ी के इस्लामिक देशों पर ईरान के हमले की निंदा नहीं करते हुए भारत में इसका विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। या पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में मारे गए मुसलमानों के पक्ष में गुहार नहीं लगा रहे।

बहरहाल शिया और सुन्नी के इस वैचारिक मतभेद के मजहबी मंथन में भारत का मुसलमान विचारो की तीव्रता में स्वयं को कटघरे में खड़ा पा रहा है। भारत में इस्लाम को मानने वाले इस विचार को समझे और उस पर गहन चिंतन कर सकते हैं कि उनके पुर्वजों ने किसका समर्थन किया था अतः किस परिवर्तन की दिशा में कदम आगे बढ़ाया था, जिस परिवर्तन के कारण मन का अंतर्द्वंद्व अस्थिर किए बैठा है।

सातवें राउंड के बाद शराब ठेकों की 15 प्रतिशत राशि हुई कम, 8 वां राउंड 27 मार्च को

माही की गूंज, झाबुआ।

एक समय ऐसा था कि, अविभाजित झाबुआ जिले का शराब का पूरा ठेका नीलामी में 9 करोड़ के करीब था। जिस समय अविनाश एंड कंपनी ने शराब के ठेके लिये थे। वहीं दूसरे वर्ष नीलामी के दौरान अविभाजित झाबुआ जिले की नीलामी प्रक्रिया 10 करोड़ के ऊपर बडा कर होने पर उस समय भी शराब ठेकेदार 10 करोड़ राशि को अविभाजित झाबुआ जिले की शराब दुकाने महंगी लगी थी और शराब दुकानो में नुकसान बताकर राशि को कम करवाने का प्रयास किया गया था।

वही अब आलीराजपुर जिला अलग हो चुका है। तथा 2026-27 के वर्ष हेतु झाबुआ जिले की 34 शराब दुकानों की 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ साढे 3 सौ करोड़ के करीब की राशि निर्धारित होने के बाद वहीं 9 करोड़ से 10 करोड़ के ऊपर हुई बढ़ोतरी की तर्ज पर शराब ठेकेदार शराब दुकानों में नुकसानी बताकर अपना पेतरा फेंकता है। और चारों तरफ ऐसा माहौल बना देता है कि, वास्तविक रूप से झाबुआ जिले की शराब दुकानों में सरकार द्वारा निर्धारित राशि अधिक है और पिछले वर्ष शराब ठेकेदारों को अत्यधिक नुकसान भी हुआ है। यह जो माहौल बनता है उससे बाहरी ठेकेदार पिछले वर्ष की नुकसानी एवं नए वर्ष में सरकार की 20 प्रतिशत वृद्धि को देखते हुए डबल नुकसान होने का अनुमान लगाता है। और इसी अनुमान के साथ बाहरी ठेकेदार झाबुआ जिले की शराब दुकानों में टेंडर डालने का प्रयास अफवाहो के चलते नही करता है।

2003 में उमा भारती की सरकार के बाद प्रदेश में एकल प्रणाली के आधार पर शराब दुकानों की नीलामी होने लगी। जिसमें सरकार का मत था कि, स्थानीय व्यक्ति एक-एक दुकान लेकर शराब का व्यवसाय करें। लेकिन इसका स्वरूप बदलकर 2 से 4 दुकानों का समूह बना दिए गए। धीरे-धीरे छोटे व्यापारी की पहुंच से यह नीलामी प्रक्रिया दूर होती गई। और चाहे अलग-अलग समूहो को अलग-अलग शराब ठेकेदार ने ठेके लिये भी हो तो झाबुआ जिले में सिडिंकेट बनाकर एक ही मैनेजमेंट के साथ शराब ठेकेदारों ने संचालन किया। ऐसे में स्थानिय मुख्य शराब ठेकेदार के रूप में अनास निवासी अलकेश बाकलिया को माना जाता है और अपने पार्टनरों के साथ यह बाकलिया पिछले कुछ वर्षों से झाबुआ जिले में शराब दुकानो का संचालन कर अपना एकाधिकार बनाए रखा है।

गुजरात सीमा से सटे झाबुआ जिले की शराब दुकानों के साथ महाराष्ट्र सीमा तक की शराब दुकाने लेता है। इस वर्ष 2026-27 के लिये भी इसी ग्रुप ने प्रथम एवं द्वितीय राउण्ड में ही झाबुआ जिले की राणापुर ग्रुप व महाराष्ट्र से सट्टे सेंधवा ग्रुप की शराब दुकानों को लिया।

वही झाबुआ जिले की बात करें तो पिछले वर्ष 2025-26 हेतु एकल प्रणाली शराब दुकान के समूह की दुकान उक्त शराब ठेकेदार ने नहीं ली थी। और इसके पहले वाले वर्ष में भी शराब दुकानों में नुकसानी शराब ठेकेदार बता रहे थे। लेकिन जब सरकार ने झाबुआ जिले के साथ पांच जिले में पूरे जिले की दुकानों की नीलामी संशोधन कर किया था। जिसके बाद यह शराब ठेकेदार जो शराब दुकानों में नुकसानी बताकर नहीं लेने वाले इन शराब के ठेकेदारों ने रायसेन के एक बड़े ठेकेदार द्वारा जिले का ठेका लेने की आशंका के तहत सरकार के 20 प्रतिशत बढ़ोतरी राशि से अधिक राशि टेंडर में डाल शराब ठेके लिये थे।

शराब ठेकों की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि, अब अलकेश बाकलिया भले ही शराब दुकानों का पार्टनर फर्म के नाम से ठेके लेकर संचालन करता है। पर अब वह सरकार को नुकसानी होने का झूठ बोलने के साथ शराब ठेकों से ही हमारा कोई लेना-देना नहीं है कि गांडु धमकिया देकर वकील पत्र तक पत्रकार को भेजता है। अब वही ग्रुप ने इस वर्ष अफवाह फैलाई की पूरे झाबुआ जिले में 2025-26 में शराब ठेको में 35 से 40 करोड़ की नुकसानी की अफवाहे उडाकर शराब के सभी समूह लेने में एतराज जताया।

वहीं जिले में पहले 9 समूह बनाए थे जिसे राणापुर शराब दुकान जाने के बाद 6टे राउंड में बच्चे 8 समूह का विभाजन कर 12 समूह बनाए गए। जिसमें एक और समूह पिटोल शराब दुकान का समूह टेंडर में लिया गया। बाकी 11 समूह की नीलामी 4 प्रतिशत कम के साथ 7 वें राउंड में 24 मार्च को भी किसी ने टेंडर नहीं डाला। जिसके बाद आबकारी विभाग ने संशोधन कर बची हुई करीब 2 सौ 60 करोड़ की शराब दुकानों की 8 वे राउंड में अगली नीलामी हेतु 15 प्रतिशत राशि संशोधन कर कम की गई।

अब देखना है जिले के कौन- कौन से समूह 27 मार्च को ई-टेंडर में ठेकेदार प्राप्त करता है, या नहीं।

नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही

माही की गूंज, करवड़।

प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रतलाम झाबुआ रोड पर स्थित मां नागणेचा काली कल्याण धाम गंगाखेडी में नवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मां नागणेचा काली कल्याणी धाम गंगाखेडी के गादीपति ने मां नागणेचा की मूर्ति संवत 1752 ई में स्थापित की गई थी। इसके बाद संवत 2034 से मां नागणेचा माता मंदिर पर शेषावतार देवश्री कल्लाजी राठौर के गादी पती महंत नारायण सिंह जी के माध्यम से मां नागणेचा माता मंदिर और कल्लाजी राठौर मंदिर का निर्माण करवाया वहीं पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है वर्तमान में गादीपत्ती प्रताप सिंह जी राठौर के द्वारा कल्ला जी के माध्यम से जनता की समस्या का निवारण किया जा रहा है। जिसमें दूर-दूर से भक्ति दर्शन लाभ लेने के लिए आ रहे हैं पूरी नवरात्रि में माताजी एवं बाबजी कल्लाजी राठौर के गादी के दर्शन के लिए भक्तों का ताता लगा रहता है। जिसमें नौ दिनों तक सत चंडी यज्ञ हवन और भक्तों की समस्या का निराकरण किया जाता है नवरात्रि में नवमी के दिन पूर्णाहुति कर भंडारा प्रसादी का वितरण किया जाता है।

कालरात्रि के रूप में माता का श्रृंगार

माही की गूंज, आम्बुआ।

इन दिनों क्षेत्र में चैत्र नवरात्र के आयोजन हो रहे, जिसके तहत माता जी के मंदिरों में माता रानी के विभिन्न रूपों में श्रृंगार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदिरा आवास फलिया में विराजमान मां बीजासन मंदिर में भी प्तिदिन नवीन श्रृंगार से माता जी को सजाया जा रहा है। बुधवार को नवरात्र के सात वें दिवस बीजासन माता का कालरात्रि स्वरुप में मन मोहक श्रृंगार किया गया। पुजारी भागीरथ चौहान ने बताया कि, विगत दिनों से बीजासन माता को विभिन्न रूपों में श्रृंगार किया जाता रहा है अभी दो दिन अष्टमी तथा नवमी को भी आकर्षक श्रंगार किया जाएगा।

अकमाल मालू को किसान कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी

माही की गूंज, झाबुआ।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार किसान कांग्रेस द्वारा मध्यप्रदेश के कई जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अकमाल सिंह मालू डामोर को झाबुआ किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मालू अकमाल की नियुक्ति से कांग्रेस ओर उनके कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। अपनी नियुक्ति पर मालू अकमाल ने बताया कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए सतत् काम कर रहे है ओर जो जिम्मेदारी पार्टी दी है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। ज्ञात रहे कि मालू इस बार कांग्रेस की ओर से पेटलावद विधानसभा के लिए बड़े दावेदार है, पिछले चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर विधानसभा चुनाव से हट गए थे। पूर्व विधायक वालसिंह मेड़ा की हार के बाद मालू की दावेदारी पेटलावद विधानसभा पर चर्चा हो रही है। पार्टी की ओर से मिली नई ओर बड़ी जिम्मेदारी को भी मालू के बढ़ते भविष्य से जोड़ कर देखा जा रहा है।

अचानक बड़ी खरीदी के चलते कई पंपों पर खत्म हुआ पेट्रोल

पेटलावद पैट्रोल पंप।

माही की गूंज, पेटलावद।

घरेलू गैस सिलेंडरो की कमी का मामला फ़िलहाल शांत हुआ भी नहीं था कि, पेट्रोल-डीजल की कमी होने की खबरे सामने आई। जिसके बाद अचानक पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतार लगने लग गई। हालत ओर भी बिगड़ने लगे जब आगे से पेट्रोल-डीजल की समस्या को देखते हुए अतिरिक्त खरीदी करना शुरू कर दी। जिसके बाद कई पंपों पर पेट्रोल खत्म होने पर पंप बंद कर दिए गए। पेट्रोल नहीं मिलने के कारण लोग पांच से दस किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ने वाले पंपों पर लोगों ने पहुंच कर पेट्रोल भरवाया। हालांकि जिला प्रशासन लगातार पेट्रोल डीजल की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने ओर अपवाहो से सावधान रहने की बात कह रहा है। पंपों पर लगी भीड़ को पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल मिल रहा है जिससे पेट्रोल या डीजल की कमी नहीं होने के प्रशासन के दावों में सच्चाई दिख रही है।

मंगलवार को अचानक पंपों पर लगी भीड़

सोमवार तक सभी सामान्य चल रहा था लेकिन मंगलवार को सुबह से पेट्रोल-डीजल की कमी होने की जानकारी फैलने लगी ओर मंगलवार शाम होते-होते पंपों पर सैकड़ों गाड़ियों की लाइन लग गई। जो देर रात तक लगी रही, तो कई पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया। लगातार किसी भी प्रकार की अफवाहो से बचने की चर्चाओं ने भी सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा लेकिन इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और मंगलवार सुबह से पंपों पर फिर से भीड़ लगना शुरू हो गई। एक दो नहीं बल्कि क्षेत्र के ज्यादातर पंपों पर यही स्थिति रही। प्रशासन के सामने इस स्थिति से निपटने की बड़ी चुनौती है।

बामनिया पैट्रोल पंप।

रोड़ निर्माण कार्य का हुआ भूमिपूजन

माही की गूंज, सारंगी।

ग्राम पंचायत बैगनबर्डी मार्ग जों कितने ही वर्षों से जीर्ण-शीर्ण हालात में था जो स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य का भूमिपूजन मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। अब मात्र एक किलोमीटर दुरी तय कर ग्रामीणजन थांदला-बदनावर हाइवे रोड़ पर आ-जा सकेगें। इस अवसर पर स्वागत भाषण मंडल अध्यक्ष पप्पू गामड़ ने दिया। कैबिनेट मंत्री भुरिया ने संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास की बात कही। उक्त आयोजन में क्षेत्र के सभी कार्यक्रता व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रताड़ना: पिता के नाम का बिजली बिल जमा नहीं हुआ तो बेटे के नाम का कनेक्शन काटा

माही की गूंज, पेटलावद।

म.प्र.पं.वि.वि.कम्पनी लिमिटेड के पेटलावद कार्यालय का मनमानी का मामला सामने आया है। जहा बिजली विभाग ने एक कनेक्शन सिर्फ उसके परिवार के दूसरे परिवार के बिल बकाया होने पर काटा दिया। जहा एक ओर हजारों लाखों के बकाया बिलो की बकाया राशि के लिए विभाग कोई कदम नहीं उठा पा रहा वही गरीब ओर मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा । जबकि यहां युवक ने दादा के नाम पर बकाया रहे बिल की आधी राशि आवेदन के साथ पिछले बकाया में से जमा कर कलेक्शन जोड़ने का आग्रह भी किया लेकिन विभाग के युवक को उल्टे पांव लौटा दिया । राजेश देवडा पिता बहादुरसिंह देवडा निवासी पेटलावद ने बताया कि नई बस्ती पेटलावद में मेरे पिता के नाम से एक विद्युत कनैक्शन जिसका की क्रमांक एन3431009733 है। जिसकी की बिल राशी 248 दिनांक 21 मार्च 2026 को मेरे द्वारा आनलाईन रूप से भर दी गई है। उसके बावजुद भी मुझ प्रार्थी के यहा का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है। जिस संबंध में मेरे द्वारा 24 मार्च को विद्युत विभाग में आकर शिकायत भी की गई थी किन्तु पुरी रात्री व बुधवार देर शाम तक भी किसी प्रकार से कोई कनेक्शन नही जोडा गया है। युवक ने बताया कि, उसके पिता वर्तमान में हृदय घात के मरींज है ओर गर्मी का मोसम होने से उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। युवक ने पिता के बीमारी के संबंधी दस्तावेज आवेदन के साथ दिए लेकिन विभाग ने युवक की एक नहीं सुनी और उसे भगा दिया। युवक ने बताया, बिल राशी भरे जाने के बावजुद भी मेरे यहा का कनेक्शन काटा गया है जबकि बिल राशी नही भरे जाने के बावजुद भी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के अनुसार कनेक्शन काटने से 15 दिन पहले नोटीस देना जरूरी होता है उसके बावजुद भी बिना कोई नोटीस के ही कनेक्शन काटा गया है। जो की विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के उल्लघन की श्रेणी में आता है।

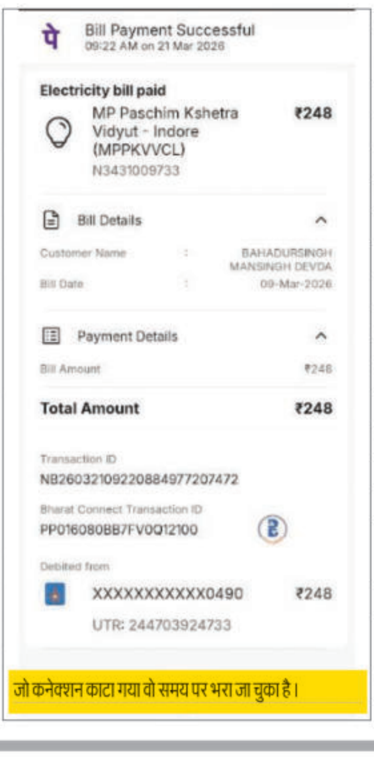
Bill Payment Successful
09:22 AM on 21 Mar 2026

Electricity bill paid
MP Paschim Kshetra Vidyut - Indore (MPPKVVCL) ₹248
N3431009733

Bill Details
Customer Name : BAHADURSINGH MANSINGH DEVDA
Bill Date : 09-Mar-2026

Payment Details
Bill Amount ₹248
Total Amount ₹248

Transaction ID
NB2603210922088497207472
Bharat Connect Transaction ID
PP016080BB7FV0Q12100
Debited from
XXXXXXXXXXX0490 ₹248
UTR: 244703924733

जो कनेक्शन काटा गया वो समय पर भरा जा चुका है।

दादा के नाम के बकाया

बिजली विभाग की मनमानी से परेशान युवक ने बताया कि, जिस बिल भुगतान बकाया बताया जा रहा है वो मेरे दादा का नाम का है जिसके पांच हजार बकाया होना बताया जिसमें से दो हजार भुगतान के बकाया राशि आने वाले बिलों के साथ भुगतान करने का भी कहा लेकिन अधिकारी ने मना करते हुए भगा दिया और पूरा बिल जमा करने पर ही कनेक्शन जोड़ने की बात कही। शिकायतकर्ता युवक ने कहा कि, वो इसकी शिकायत कलेक्टर ओर जन सुनवाई तक करेंगे। साथ ही बीमार पिता के साथ किसी भी प्रकार की गर्मी के कारण तबियत खराब होती है या फिर कोई भी घटना होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होने की बात कही।

श्री राठौर के प्रयास से बच्चे को मिला नया जीवन

माही की गूंज, सारंगी।
संजय उपाध्याय।

ग्राम बोड़ायता निवासी अग्निनारायण सिंह राठौर ने एक बच्चे को डॉक्टरों की सलाह मानकर नया जीवन दिया। ग्राम मातारुण्डी ग्राम पंचायत मोहनपुरा में निवास करते हैं बच्चे के पिता ईश्वर भूरिया व परिवार मजदूरी करते हैं इनका दो वर्ष का पुत्र अजय भूरिया के दोनों वाल में छेद होने से हमेशा बीमार रहता था। जब यह बात भाजपा कार्यकर्ता अग्नि नारायण सिंह राठौर को पता चली तो बच्चों के माता-पिता को साथ में लेकर सिविल हॉस्पिटल पेटलावद ले गए। यहा बीएमओ डॉक्टर एमएल चोपड़ा ने जांच करने के बाद एनआरसी में भर्ती किया। असके बाद उपचार के बाद भी एक सप्ताह में बच्चे का वजन नहीं बढ़ा। जिसके बाद डॉक्टर चोपड़ा ने बच्चे के माता-पिता एवं अग्नि नारायण सिंह राठौर को बच्चों की बीमारी के बारे में बताया और उन्होंने इंदौर डॉक्टर से संपर्क कर इंदौर बताने की सलाह पर इंदौर गए। जहा डॉक्टर ने सारी जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट में बच्चे के वाल में छेद बताया और ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। उपचार का पुरा खर्च करिब 5 लाख रूपए स्वयं राठौर ने दिये। तथा सफ़ल ऑपरेशन डॉक्टर द्वारा किया गया।

संपादकीय

बीमा कंपनियों व अस्पतालों का मकड़जाल

बीमा कारोबार की जटिलताएं हमेशा से ही आमजन के लिए एक अनसुलझी गुत्थी रही हैं। हमारी भविष्य की आशंकाओं व भय पर फल-फूल रहे इस कारोबार को लेकर गाहे-बगाहे परेशान करने वाली खबरें आती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद तेजी से फल-फूल रहे विभिन्न बीमा कारोबारों की विसंगतियां कम नहीं हुई हैं। इसी तरह मेडिकल बीमा को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आती रही हैं। दरअसल, लगातार महंगी होती चिकित्सा सुविधाओं के दौर में, भविष्य में महंगे इलाज का खर्च उठाने का भरोसा दिलाकर बीमा कंपनियां लोगों को बीमा पॉलिसियां खरीदने को मानसिक रूप से तैयार कर लेती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जब वास्तव में कोई बीमार पड़ता है तो इलाज पर हुए खर्च के भुगतान को लेकर तमाम किंतु-परंतु बीमा कंपनियां करने लगती हैं। कई खामियां निकाली जाती हैं, जिनके बारे में बीमा धारक को पता ही नहीं होता है। कई बार तो छिपे-ढके कारण बताकर चिकित्सा खर्च की भरपाई करने से भी मना कर दिया जाता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीए के आंकड़ों ने बीमा कंपनियों के मुनाफा खेल को उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 में छब्बीस हजार करोड़ रुपये के बीमा दावे खारिज किए गए थे। निस्संदेह, ये आंकड़ा बीमा कंपनियों तथा पांच सितारा अस्पताल प्रबंधकों के अपवित्र गठबंधन को ही दर्शाता है। बाकायदा पिछले दिनों राज्यसभा में निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के अपवित्र गठजोड़ का मामला उठाया गया। जो हर साल हजारों लोगों को कर्ज व गरीबी की दलदल में धकेल देता है। अक्सर आरोप लगता है कि मरीजों को उपचार के मुकाबले बेहद कम राशि का भुगतान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों व बीमा कंपनियों के मध्य सांठगांठ के मामले सामने नहीं आते। लेकिन हमारा नियामक-तंत्र सारे घटनाक्रम की अनदेखी कर देता है। विडंबना यह भी है कि केंद्र व राज्य सरकारों के स्तर पर भी इस मुनाफाखोरी पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया जाता है, जिससे लोगों को उलटे उस्तरे से मूंडने का खेल बदस्तूर जारी रहता है।

दरअसल, लोग जब कोई स्वास्थ्य बीमा कराते हैं तो उन बारीकियों के बारे में नहीं बताया जाता है, जिसके आधार पर मरीजों के चिकित्सा बीमा राशि को खारिज किया जाता है। अक्सर इलाज के बड़े खर्चे के दावे को कई मीन-मेख निकालकर नकार दिया जाता है। कई बार तो अमानवीयता की हदें भी सामने आती हैं जब मरीज की मृत्यु पर, खर्च चुकाने में असमर्थ होने पर अस्पताल प्रबंधक परिजनों को पार्थिव शरीर तक को देने से मना कर देते हैं। जबकि इस बारे में अदालत व सरकार की तरफ से सख्त आदेश हैं कि बकाया राशि के लिए किसी मरीज के शव को रोका नहीं जा सकता। दरअसल, चिकित्सा बीमा आज देश-दुनिया में बड़ा कारोबार बन गया है। लेकिन पश्चिमी देशों में भुगतान में ईमानदारी व कार्यशैली में पारदर्शिता से इस व्यवसाय का विस्तार हुआ है। लेकिन भारत में ईमानदारी, पारदर्शिता के अभाव व दोषपूर्ण कार्यशैली से चिकित्सा बीमा के औचित्य पर ही सवाल उठते हैं। सवाल उन सरकारी विभागों पर भी है, जो बीमा कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने की पहल नहीं करती। तभी साल में करोड़ों रुपये की उगाही करने वाली बीमा कंपनियां कई तकनीकी वजहों से मरीज के इलाज में लगी रकम का बड़ा हिस्सा देने से मना कर देती हैं। वास्तव में जरूरत इस बात की है कि बीमा कराते वक्त ईमानदारी से बीमे से जुड़ी शर्तों से उपभोक्ता को अवगत कराया जाए। लेकिन इससे जुड़े जटिल व अस्पष्ट नियमों को पारदर्शी ढंग से समझाया ही नहीं जाता, जिसको वे बाद में इलाज कराने के उपरांत भुगतान रोकने का जरिया बना लेती हैं। जिसके चलते अक्सर अस्पताल में भर्ती होने पर आए खर्च और बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान की गई राशि में बड़ा अंतर नजर आता है। निस्संदेह, देश में इस दिशा में उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच होनी चाहिए कि मरीजों को बीमे का कितना लाभ मिला और अस्पताल तथा बीमा कंपनियों के मुनाफे का स्तर क्या रहा। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए निगरानी हेतु एक राष्ट्रीय तंत्र बनाया जाना जरूरी है।

वक्त बदला है तो सास को भी बदलना होगा

पिछले दिनों अपने इसी अखबार के प्रथम पृष्ठ पर एक दिलचस्प खबर पढ़ी। इसमें बताया गया कि पंजाब के बठिंडा जिले के बल्लो गांव की पंचायत ने बेस्ट सास अवार्ड शुरू किया है। इसकी पहल गांव की सरपंच अमरजीत कौर ने की। इसे प्रति वर्ष आठ मार्च को यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। छह महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। यह पुरस्कार किन महिलाओं को दिया जाए, इसके लिए पूरे गांव से रिपोर्ट ली जाएगी। बहुओं और पड़ोसियों की राय पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरपंच अमरजीत कौर ने यह भी कहा कि इससे पारिवारिक सम्बंध मजबूत होंगे। समझदार सास घर की नींव होती है, जो अपनी बहू को अपनाकर घर को स्वर्ग बना देती है। इस अवसर पर सबसे अधिक पुस्तकें पढ़ने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। अपने समाज में लड़की को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उसे पराए घर जाना है। पराए घर जाकर सास से निपटना है। सास की तस्वीर बहुत डरावने ढंग से पेश की जाती थी।

बचपन की एक घटना अक्सर याद आती है। छठी कक्षा में पढ़ती थी। लड़कियों का स्कूल था। वहां एक बहुत वृद्ध महिला गणित पढ़ातीं। सफेद साड़ी ही पहनतीं। उनके बाल भी एकदम सन से सफेद थे। एक दिन गणित पढ़ाते-पढ़ाते, वे हम सब लड़कियों से कहने लगीं कि सिर्फ गणित पढ़ने से ही, सब कुछ नहीं होगा। जब ससुराल जाओगी तो वहां कैसे जीना है, यह सीखना पड़ेगा। एक लड़की ने पूछा कि बहन जी क्या सीखना होगा। तब वह हंसते हुए बोलीं कि सास के लिए इम्तिहान में पास होना। कैसा इम्तिहान, तो उन्होंने बताया कि हर सास का इम्तिहान लेने का तरीका अलग-अलग होता है। जैसे कि मेरी शादी जब हुई तो मैं बारह साल की थी। शादी के अगले दिन ही सास ने गेहूं और बाजरा मिलाकर सामने रख दिया कि इसे अलग-अलग करो। शाम तक काम पूरा करना है। घर के और काम भी थे। शाम क्या, पूरी रात हो गई, फिर भी नहीं कर पाई। इसी तरह एक

दिन नमक और चीनी मिलाकर रख दी। नमक में से चीनी बीननी थी। शर्त यह भी थी कि चीनी से एक भी नमक का दाना चिपका नहीं रहना चाहिए।

उनकी बातें सुनकर घबराहट-सी होने लगी। घर जाकर मां को सारी बात बताई। यह भी पूछा कि क्या अम्मा (दादी) भी तुम्हारे साथ ऐसा करती थीं। मां ने हंसकर कहा, तेरी अम्मा बड़ी कठोर स्वभाव की थीं। बहुओं को पर्दे में रखती थीं, उनकी हर बात को मानना भी पड़ता था, मगर ऐसा कभी नहीं किया। ये तो टाइम खराब करना हुआ कि बाजरे में गेहूं मिला दो और चीनी में नमक। इससे तो गेहूं साफ ही करा लिए जाते, जिससे कि काम बचता। और नमक से चीनी चाहे जितनी अलग कर ली हो, नमकीन हो गई होगी। मां ने चाहे जितना समझाया, लेकिन सास की तस्वीर ऐसी बनी रही। बड़ी होकर जब भी साथ की किसी लड़की की शादी होती और वह कहती कि उसकी सास बहुत अच्छी हैं, तो लगता कि झूठ बोल रही है। क्योंकि मान लिया था कि सास खराब ही होती हैं, जो अक्सर दिखता भी था।

पुराने जमाने की हिंदी फिल्मों में भी ललिता पंवार मार्का सासें दिखाई देती थीं। जिनका पहला और आखिरी काम यही होता था कि वे बहू को कैसे सताएं। इसके लिए वे अपने बेटों को बहू को पीटने और शारीरिक हिंसा करने के लिए भी उकसाती थीं। जब बहू पिटती थी, दर्शक तालियां बजाते थे। ये वे बहुएं होती थीं, जिन्हें घुट्टी में पिलाया जाता था कि जिस घर में डोली गई, वहां से अर्थी ही उठे। ये अभागी महिलाएं करतीं भी क्या, क्योंकि शादी के बाद इन्हें अपने परिवार वाले भी ससुराल के भरोसे छोड़ देते थे। तलाक लेना बहुत बदनामी का कारण बनता था। ये बहुएं न शिक्षित थीं और न ही आत्मनिर्भर। आखिर जाती भी कहां। इसलिए सास और ससुराल को सहने और समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था।

और तो और बहुत से परिवारों में गैस होते हुए भी अक्सर स्टोव बहुओं पर फट जाते थे। स्टोवों को भी मालूम था कि उन्हें बस बहुओं पर ही फटना है। अक्सर दहेज हत्याएं ऐसे ही की जाती थीं। इस संदर्भ में महान लेखिका महादेवी वर्मा का संस्मरण भाभी इतना मार्मिक है कि पढ़ते हुए आंसू बहने लगते हैं। यहां बहू को सताने के लिए सास नहीं, ननद है, वह भी विवाहित। जो जब आती है, तब अपनी विधवा भाभी को बुरी तरह से पीटती है, उसे जगह-जगह जलाती है। और उन्नीस साल की विधवा स्त्री, यह सब झेलने को मजबूर है।

इन सासों की मानसिकता पर ध्यान दें, तो ये अपनी सास के अत्याचार का बदला, बहुओं से लेती थीं। जो इन्होंने सहा, बहू भला उससे कैसे बचे और क्यों बचे। जबकि कायदे से होना यह चाहिए था कि जो अपमान, अत्याचार, जिल्लत, इन्होंने सही, वह बहू को न सहनी पड़े और एक तरह से अत्याचार का सिलसिला थमे। संयुक्त परिवारों की ये ऐसी आफतें थीं, जिनका शिकार बहुएं होती थीं। दहेज का तड़का इन अत्याचारों को बेतहाशा बढ़ाता था।

इन दिनों भी बहुत-सी रील्स और वीडियो ऐसे दिखते हैं, जहां हर बात पर सास बहू को सताते दिखाई देती है, लेकिन अंत तक आते-आते सास का हृदय परिवर्तन हो जाता है।

आज वक्त बदला हुआ है। लड़कियां पढ़-लिख गई हैं। अपने पांवों पर खड़ी हैं। गांव-गांव लड़कियों की आत्मनिर्भरता को परिवार और समाज ने स्वीकार कर लिया है। उनकी शिक्षा चलती रहे, इसके लिए उन्हें तरह-तरह की सरकारी सहायता मिलती है। उनकी रक्षा के लिए बहुत से कानून भी हैं। और तो और संसद में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है। अब लड़कियां वह नहीं रहीं, जैसी ससुराल वाले उन्हें देखना चाहते हैं।

क्षमा शर्मा

यदि वैवाहिक विज्ञापनों पर नजर डालें, तो अब भी फेयर एंड लवली, होमली कन्या चाहिए। पता नहीं इस होमली की क्या परिभाषा है। रील्स और वीडियो की मानूं तो ये कि बहू खूब पैसे भी कमाए, लेकिन अपनी तनख्वाह पति या सास के हाथों में दे। कपड़े ऐसे पहने, जो सास को पसंद हों। सवेरे जल्दी उठकर घर का काम निपटाकर जाए और आकर काम निपटाए। इसीलिए इन दिनों परिवार का ढांचा जल्दी ही टूट जाता है। बहुत से जोड़े जल्दी ही घर वालों से अलग रहने लगते हैं। ऐसा नहीं होता, तो तलाक ले लेते हैं। बढ़ते तलाक का एक बड़ा कारण भी परिवार वालों की भूमिका है। कुछ दिन पहले एक अध्ययन में बताया गया था कि तलाक के मामलों में अब लड़कियां पहल कर रही हैं। वे ऐसे सम्बंध में नहीं रहना चाहतीं, जो उन्हें पसंद न हो। कई बार शादी के एक-दो दिन बाद ही वे ससुराल लौटने से मना कर देती हैं।

हालांकि, अब महानगरों में बहुओं की पारंपरिक छवि टूट चुकी है। यों भी इन दिनों की नौकरियां ऐसी नहीं हैं कि नौकरी भी कर लो और घर के काम भी निपटा लो। इसलिए सहायक-सहायिकाओं की मदद लेनी पड़ती है।

बड़ी है कामयाबी अब जश्न मनाने का वक्त

उठ गैसजली उठ! देख, तेरा योद्धा गैस सिलेंडर विजेता बनकर आया है। उठकर मेरा विजय तिलक कर। घर में गैस का सिलेंडर आने पर मंगल गीत गा। मोहल्ले में लड्डू बांट। आज की तारीख में जो गैस का सिलेंडर अपने घर ला रहा है, वह विजेता माना जा रहा है। सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लग पेशेंस के साथ अपनी बारी का इंतजार करना बच्चों का खेल नहीं। अगर किसी की पेशेंस को मापना हो तो उसे गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया जाए।

आंखें खोलकर देख, गैस के सिलेंडर के लिए चारों ओर कितना हाहाकार है? जनता का घरेलू गैसीय क्रंदन सुन! सरकार का गैस मल्हार सुन!

जिनके घरों में गैस सिलेंडर भरे हैं, वे अपने गैस सिलेंडरों के पास दिन-रात ठीकरी पहरा दे रहे हैं। जिनके पास लॉकर हैं, उनमें अपने भरे गैस के सिलेंडरों को लॉक करके रखा है। जो जैसे-कैसे घर गैस के भरे सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, वे कड़ी सुरक्षा के बीच अपने कंधे पर गैस सिलेंडर उठाए आ रहे हैं। क्या पता रास्ते में कौन कच्छाधारी गिरोह उनका सिलेंडर लूट ले।

गैस संकट के बीच जिधर देखो, वहीं गैस का काला बाजार है। आईसीयू से अधिक वेटिंग गैस के सिलेंडर की चल रही है।

देख पगली! कल तक जो लकड़ियों पर रोटी बनाने के नुकसान गिनाते नहीं थकते थे, आज वही गैस की किल्लत से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनहित में लकड़ियों पर बनी रोटी के फायदे गिनाने लगे हैं। मीडिया वाले टीवी पर लकड़ियों के चूल्हे पर बनती रोटियों की एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाने लगे हैं। टीआरपी ऐसे ही बढ़ती है।

अशोक गौतम

डियर गैसजली! अब घर में गैस आ गई है। किचन हंस रहा है। गैस का चूल्हा हंस रहा है। अंग-अंग टूटा होने के बाद भी मैं हंस रहा हूं। तू हंस रही है, पर पड़ोसी रो रहा है। उसे लगता है मेरे हाथ बहुत लंबे हैं।

घर में गैस सिलेंडर आ जाने पर मैं लंबी लाइन में लगने की थकान भूल गया हूं। घर में गैस का सिलेंडर आ जाने पर अब तुझे बेड-टी पिलाने के बाद तुझे जागृति का मधुर गीत सुनाते-सुनाते जगाऊंगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आज जो तू कहेगी वही तेरे लिए बनाऊंगा। मैं तेरी पसंद से बाहर थोड़े ही हूं पगली! लंच करने के बाद पड़ोसी के घर उसकी किचन के हाल देखने चलेंगे।

न्याय की सुलभता ही कानूनी शिक्षा का मकसद

भारत में कानूनी शिक्षा को केवल एक स्नातक डिग्री हासिल करने के माध्यम के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक जीवंत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य ऐसे सजग 'सोशल इंजीनियर' तैयार करना है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिला सकें। हाल ही में अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ (2026) मामले में उच्चतम न्यायालय की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। स्पष्ट किया कि कानूनी शिक्षा जैसे नीतिगत मामलों में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाएगा।

यह वक्तव्य संकेत करता है कि वर्तमान में जारी 4 साल बनाम 5 साल की अवधि का विवाद केवल समय की गणना का नहीं, बल्कि 'गुणवत्ता, सार्थकता और परिपक्वता' का है। कानून कोई यांत्रिक या तकनीकी विषय नहीं जिसे सिर्फ सूत्रों से समझा जा सके; यह समाज, संस्कृति व नैतिकता के ताने-बाने से बुना हुआ है। सफल 'विधिवेत्ता' बनने के लिए छात्र को वे सामाजिक मूल्य आत्मसात करने हेतु पर्याप्त 'मानसिक स्पेस' व समय चाहिये।

भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण देश में कानूनी शिक्षा का स्वरूप अनिवार्य रूप से 'न्याय की सुलभता' पर केंद्रित होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का बड़ा दोष है कि यह मुख्यतया कॉर्पोरेट घरानों व उच्च न्यायालयों के लिए वकील तैयार करती है। हमें यह ढांचा बदलने की जरूरत है ताकि वकीलों को ग्रामीण और जिला स्तर की अदालतों के लिए भी समान रूप से तैयार किया जा सके। इसके लिए 'लोक अदालत' और 'मध्यस्थता' जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को पाठ्यक्रम का अनिवार्य और व्यावहारिक हिस्सा बनाना होगा। क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों की भूमिका यहां और भी अहम हो जाती है। उन्हें स्थानीय विधिक समस्याओं, जैसे ग्रामीण भूमि विवाद, पारिवारिक उत्तराधिकार और सामुदायिक न्याय प्रणालियों पर 'क्लीनिकल रिसर्च' को बढ़ावा देना चाहिए। जब तक कानून का छात्र जमीन से नहीं जुड़ेगा, न्याय की वास्तविक अवधारणा को नहीं समझ पाएगा।

वैश्विक परिदृश्य में देखें तो कानूनी शिक्षा का ढांचा इस बुनियादी प्रश्न पर टिका है कि इसे 'सामान्य स्नातक' माना जाए या 'विशेषज्ञता वाला पेशा'। भारत में 5-वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम सबसे लोकप्रिय है, जो छात्र को शुरू से ही कानूनी परिवेश में ढाल देता है। इसके उलट, अमेरिका में कानून 'पोस्ट-ग्रैजुएट' शोध विषय है। पश्चिमी देशों में कानून 'अकादमिक अनुसंधान' का विषय है, जबकि भारत में इसे 'व्यावसायिक कौशल' तक सीमित कर देते हैं। विकसित देशों के संस्थान 'विधिक तर्कशीलता' के साथ ही 'विषयांतर अनुशासनात्मक' शिक्षा पर बल दे रहे हैं। हमें भी अब कानून को डेटा साइंस, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ाना होगा। अंतरिक्ष कानून, ऊर्जा कानून और खेल कानून जैसे उभरते क्षेत्रों को अपनाना वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने को अनिवार्य है।

मौजूदा दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने विधिक शोध और दस्तावेज लेखन बेहद सरल बना दिया। कानून से जुड़े बुनियादी कार्य मशीनों द्वारा किए जाने की प्रबल संभावना है। चुनौती 'मानवीय विवेक बनाम मशीन' की है। अधिवक्ताओं को 'मशीनी निर्भरता' पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। मशीनी एल्गोरिदम जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन उस 'मानवीय अंतर्दृष्टि' और 'व्यावसायिक नैतिकता' का स्थान नहीं ले सकते जो एक जटिल मामले में न्यायपूर्ण निर्णय के लिए जरूरी होती है। इसलिए, पाठ्यक्रम में 'विधिक तकनीक', 'डिजिटल नैतिकता' और 'साइबर सुरक्षा कानून' को अनिवार्य शामिल करना चाहिए। सफल अधिवक्ता वही होगा जो तकनीक को 'गुलाम' की तरह उपयोग करे, न कि उसका गुलाम बन जाए। 'लीगल डिजाइन थिंकिंग' का उपयोग कर कानून की जटिलताओं को सरल बनाकर आम आदमी के लिए सुलभ बना सकते हैं।

भारतीय कानूनी जगत की विडंबना है कि न्याय की भाषा आज भी मुख्यतः अंग्रेजी है, जबकि बहुसंख्यक आबादी इस भाषा से अपरिचित है। 'बहुभाषी शिक्षा' और 'कानूनी अनुवाद' को बढ़ावा देना समय की मांग है। वास्तविक विधिक क्रांति तब आएगी जब एक वकील अपनी स्थानीय भाषा में जटिल कानूनों को समझा सके और न्यायालय में पैरवी कर सके। शिक्षा का माध्यम ऐसा हो जो भाषाई बाधाओं को तोड़ कानून की समझ को सर्वव्यापी बनाए। जब तक कानून की पढ़ाई बोझिल और औपनिवेशिक शब्दावली से मुक्त नहीं होगी, तब तक यह समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए 'अनसुलझी पहेली' रहेगी।

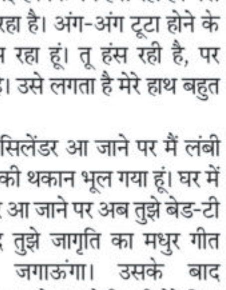
डॉ. सुधीर कुमार

जैसे मेडिकल छात्र के लिए अस्पताल में बिताया गया समय उसके कैरियर की नींव होता है, वैसे ही लॉ छात्रों के लिए 'लीगल एड क्लीनिक्स' और 'मूट कोर्ट्स' वास्तविक पाठशालाएं हों। छात्रों को वास्तविक मुकदमों, क्लाइंट काउंसलिंग और कानूनी ड्राफ्टिंग का व्यावहारिक अनुभव मिले। पाठ्यक्रम में छात्रों के 'मानसिक स्वास्थ्य' और 'वर्क-लाइफ बैलेंस' पर भी ध्यान दिया जाए। 'एल्गोरिदम की समझ' और 'ऑनलाइन विवाद समाधान' के इस युग में सफलता का मंत्र अब केवल 'किताबी ज्ञान' नहीं, बल्कि 'तकनीकी निपुणता' और 'व्यावहारिक कौशल' का मेल है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज (2023) के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा मानकों में सुधार न्यायिक ढांचे के लिए अपरिहार्य है। विश्वविद्यालयों को अब 'वकीलों की फौज' पैदा करने वाली फैक्टरी बनने से रुकना होगा। हमें ऐसे 'नीति निर्माता' और 'न्याय के प्रहरी' तैयार करने हैं जो न केवल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों, बल्कि अपनी मिट्टी और सामाजिक समस्याओं से भी गहरे जुड़े हों।

मंडी में गेंहूं की बंपर आवक, करना पड़े गेट बंद

माही की गूंज, रतलाम।

शहर के महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी में इन दिनों गेहूं की बंपर आवक होने से व्यवस्था गड़बड़ा गई हैं, किसानों को दिन भर मंडी गेट के बाहर सडक़ किनारे भरी दोपहरी में उपज भरे ट्रक लेकर खड़ा रहना पड़ रहा हैं, क्योंकि दो दिन से अधिक आवक के कारण मंडी गेट बंद करना पड़ रहे हैं। मंगलवार को 125 से अधिक किसान अपनी ट्राली लेकर दिन भर गर्मी में सडक़ किनारे खड़े रहें, कुछ व्यापारी अब भी अपना माल शेड और छपरों पर जमाए है, वह समय पर हट जाए तो किसानों को उपज लेकर चिलचिताली धूप में नहीं खड़ा रहने पड़े।

लगता रहा जाम

दिन में एक किसान ने अन्य जिलों से आ रहे किसानों की ट्रालियों का विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे महू-नीमच रोड मंडी गेट के बाहर दोनों तरफ लम्बा जाम लग गया। किसान को समझाकर अंदर ले जाने का बाद मामला शांत हुआ और जाम खुलवाया। किसान का कहना था मेरा तीन दिन में नंबर आ रहा है इसलिए उज्जैन-धार जिले वाले की ट्राली नहीं लें।

600 से अधिक ट्राली मंडी में खड़ी

कृषि उपज मंडी प्रांगण प्रभारी राजेंद्र व्यास ने बताया कि नीलामी के बाद शाम 6 बजे तक 600 से अधिक करीब ट्राली मंडी प्रांगण में गेहूं की खड़ी थी। दिन भर में 454 ट्राली नीलाम हुई। शाम 5 बजे गेट खोलकर बाहर खड़ी ट्रालियों को अंदर लिया। अब 25 मार्च को मंडी चालू रहेगी, इसके बाद 28 मार्च को केवल गेहूं नीलाम होंगे। शेष दिन अवकाश के कारण 3 अप्रेल तक मंडी में नीलामी नहीं होगी।

28 मार्च को केवल गेहूं की नीलामी

मंडी सचिव किशोरकुमार नरगावे ने बताया कि 26 मार्च को अष्टमी, 27 को रामनवमी का अवकाश रहेगा। 28 को केवल गेहूं की नीलामी होगी। 29 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा। 30 मार्च को बैंकों की वार्षिक लेखा बंदी, 31 को महावीर जयंती एवं 1 अप्रेल को बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी व्यापारी एसोसिएशन के आवेदन, 2 अप्रेल को हनुमान जन्मोत्सव, 3 अप्रेल को गुड फ्राइडे का शासकीय अवकाश रहेगा। इस दौरान अनाज-लहसुन-प्याज मंडी एवं उप मंडी नामली प्रांगण का अवकाश रहेगा।

जिला पंचायत अध्यक्ष में हुई सुलह

माही की गूंज, रतलाम।

सोमवार को कलेक्ट्रेट में धरने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई चंद्रवंशी और कलेक्टर मिशा सिंह के बीच आखिरकार समन्वय बन गया। मंगलवार शाम करीब पांच बजे भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जिपं अध्यक्ष लालाबाई को साथ लेकर कलेक्टर मिशा सिंह से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके पति शंभूलाल भी मौजूद रहे। करीब 20 मिनट तक कलेक्टर चैंबर में चली चर्चा के बाद बाहर आए भाजपा जिलाध्यक्ष ने अब सब कुछ ठीक होने की बात कही।

उपाध्याय ने बताया कि, गत दिवस समन्वय की कमी के चलते ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन अब सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी मुद्दों पर चर्चा हो गई है। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए संगठन स्तर पर भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

गौरतलब है कि सोमवार रात करीब आठ बजे जिपं अध्यक्ष लालाबाई चंद्रवंशी कलेक्ट्रेट परिसर में सीढ़ियों पर पति शंभूलाल के साथ धरने पर बैठ गई थीं।

उनका आरोप था कि कलेक्टर द्वारा पूरे दिन मिलने का समय नहीं दिया गया। करीब एक घंटे तक चले धरने के बाद एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा के बाद धरना समाप्त कर दिया गया था।

सुबह से शाम तक इंतजार कराने का आरोप

जिपं अध्यक्ष ने सोमवार सुबह ही कलेक्टर से मिलने का समय मांगा था। वे गांव से जुड़े मुद्दों और अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा करना चाहती थीं, लेकिन शाम तक मुलाकात नहीं हो सकी। इस पर आक्रोशित होकर वे धरने पर बैठ गईं। उनके पति एवं सांसद प्रतिनिधि शंभूलाल ने आरोप लगाया था कि सुबह 11 बजे आवेदन देने के बाद भी शाम सात बजे तक इंतजार कराया गया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।

इन मुद्दों को लेकर थी नाराजगी

शंभूलाल के अनुसार, गांव के मंदिर से जुड़े मामले, एक युवती की गुमशुदगी पर एक माह तक कार्रवाई नहीं होने सहित अन्य विषयों को लेकर कलेक्टर से मिलने का प्रयास किया गया था। गुमशुदा युवती के मामले में बिलपांक थाना प्रभारी को दो दिन में ठोस कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। मंगलवार को हुई मुलाकात के बाद दोनों पक्षों के बीच स्थिति सामान्य होती नजर आई। भाजपा जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अब सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है और मामला सुलझ गया है।

अवैध मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई

माही की गूंज, मंदसौर।

पुलिस द्वारा प्रदेशभर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आगर मालवा एवं मंदसौर जिलों में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाते हुए 13 क्विंटल से अधिक का अवैध डोडाचूरा एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहनों सहित लगभग एक करोड़ 72 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस मुख्यालय द्वारा जानकारी दी कि, आगर मालवा जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आगर-सारंगपुर मार्ग स्थित गणेश घाटी पर नाकाबंदी कर एक कंटेनर ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान कंटेनर में भरी 31 काले रंग की बोरियों में छिपाकर रखा गया कुल 613 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद किया। प्रकरण में 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो वाहन के माध्यम से मादक पदार्थ को अन्य राज्य की ओर परिवहन कर रहा था। आरोपी के कब्जे से कंटेनर ट्रक, 02 मोबाइल फोन, नगद राशि एवं अन्य दस्तावेज सहित लगभग 1 करोड़ 53 लाख 46 हजार रुपये की संपत्ति जप्त की है।

वहीं, मंदसौर जिले के थाना सीतामऊ क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम मानपुरा आम रोड से एक बोलेरो पिकअप वाहन की तलाशी के दौरान 37 प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ कुल 7 क्विंटल 22 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त किया। उक्त कार्रवाई में 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा बोलेरो पिकअप वाहन, एक ट्रैक्टर एवं मोबाइल फोन सहित लगभग 19 लाख 3 हजार रुपए मूल्य की संपत्ति जप्त की गई है। दोनों प्रकरणों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है तथा मादक पदार्थ के स्रोत एवं तस्करी नेटवर्क के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है तथा इस प्रकार के अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।

मधुमखक्खियों के हमले में 24 भेड़ों की मौत

माही की गूंज, शाजापुर/शुजालपुर।

तिलावद पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम सलकनखेड़ी में मधुमक्खियों के हमले से 24 भेड़ों की मौत हो गई और चरवाहा गंभीर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले भी एक घटना में 220 भेड़ों की मौत हो गई थी। ऐसे में राजस्थान से आए चरवाहे दुखी हैं। उनका कहना है कि दोनों घटनाओं से उन्हें काफी नुकसान हुआ है।

उन्होंने प्रशासन से मुआवजा के रूप में राहत देने की गुहार लगाई है। मृत भेड़ ग्राम सकलनखेड़ी क्षेत्र में मौके पर ही पड़ी हैं। घायल चरवाहे हरतीगा रामदेवासी निवासी ग्राम काम्बा, तहसील आहोर, जिला जालौन राजस्थान का सीहोर में अस्पताल में उपचार चल रहा है। हरतीगा तीन साथियों के साथ मध्य प्रदेश में 350 भेड़ें लेकर आया था, किंतु दो हादसों में उसकी 250 से ज्यादा भेड़ की मौत हो गई है।

राजस्थान के चरवाहे भेड़ों को लेकर एमपी में आते हैं

तिलावद पुलिस चौकी को मामले की जानकारी लगी। पशु चिकित्सक को सूचना देकर मौके पर भेजा गया। चिकित्सक ने टीम के साथ भेड़ों का पोस्टमार्टम किया। चौकी प्रभारी घनश्याम बैरागी ने बताया कि पशु चिकित्सा विभाग को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराया गया।

राजस्थान के चरवाहे भेड़ों को लेकर प्रदेश में आते हैं। हरतीगा राम ने बताया कि तीन साथियों के साथ तीन माह भेड़ों के साथ मध्य प्रदेश में हैं। 25 फरवरी को साप्ताहिक बाजार से खरीदी गई मिलावटी हल्दी खिलाने के बाद 220 भेड़ों की मौत हो गई थी।

पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह से हड़कंप, पंपों पर उमड़ी भारी भीड़

माही की गूंज, रतलाम।

एलपीजी गैस संकट के बाद अब शहर में पेट्रोल और डीजल को लेकर अफवाहों ने माहौल गरमा दिया है। सोमवार रात से ही पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई, जिससे कई पंपों का स्टॉक समाप्त हो गया और अधिकांश पंप समय से पहले बंद करने पड़े। इसके चलते मंगलवार को हालात और बिगड़ गए।

टैंकरों की सप्लाई और अफवाहों का असर

बताया जा रहा है कि, ऑयल कंपनियों के डिपो द्वारा एडवांस में टैंकर नहीं छोड़े जाने की स्थिति भी सामने आई। इसी बीच पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाह फैलते ही लोगों ने बड़ी संख्या में पंपों का रुख किया। परिणामस्वरूप कई स्थानों पर लंबी कतारें लग गईं और पेट्रोल भरवाने को लेकर विवाद की स्थिति भी बनी।

स्टॉक खत्म होने से बंद हुए कई पंप

सोमवार रात बंद हुए पेट्रोल पंप मंगलवार को डिपो से सप्लाई मिलने के बाद दोबारा शुरू तो हुए, लेकिन दिनभर भीड़ का दबाव बना रहा। शहर के लगभग 10 से 12 पेट्रोल पंपों पर यही स्थिति देखने को मिली।

जिले में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध

इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद गोले ने स्पष्ट किया कि जिले में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। ऑयल कंपनियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 मार्च की स्थिति में जिले के 184 पेट्रोल पंपों पर 13 लाख 26 हजार लीटर पेट्रोल और 16 लाख 16 हजार लीटर डीजल उपलब्ध है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें और पेट्रोल-डीजल को लेकर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें।

भगवान महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव 31 मार्च से

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में 31 मार्च को नयापुरा रोड स्थित रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन (माहेश्वरी धर्मशाला) में सकल जैन समाज के द्वारा भगवान महावीर का जन्मकल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जाना है। रूद्राक्ष माहेश्वरी भवन में आने वाले गणमान्य महानुभावों व माता बहनों के लिये उनके वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था कालाखेत खेल मैदान में की जायेगी। कालाखेत खेल मैदान में पार्किंग की व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से हो तथा पार्किंग करने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नं आए, इसके लिये मंगलवार को नपाध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, सकल जैन समाज अध्यक्ष लोकेन्द्र जैन गोटावाला ने नपा के जनप्रतिनिधियों एवं सकल जैन समाज के नव मनोनीत पदाधिकारियों के साथ कालाखेत खेल मैदान का निरीक्षण किया।

नपाध्यक्ष ने इस मौके पर प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी हेमन्त शर्मा, समयपाल पंकज साकी को बुलाकर यह निर्देश दिये कि समय से पूर्व इस खेल मैदान की सफाई का कार्य किया जाये तथा जहाँ भी लाईनिंग आदि आवश्यक कार्य करने हो यह कार्य भी सकल जैन समाज की मंशा के अनुरूप किया जाये। खेल मैदान में यदि समतलीकरण करना हो तो भी जेसीबी आदि का उपयोग कर यह कार्य शीघ्रता से किया जाये ताकि पार्किंग की व्यवस्था पूरी चाक-चौबंद हो पाये। निरीक्षण के मौके पर नपा सभापति निलेश जैन, रमेश ग्वाला भी साथ थे।

सकल जैन समाज अध्यक्ष लोकेन्द्र जैन गोटावाला ने कहा कि 30 मार्च को रात्रि 8 बजे माहेश्वरी भवन में सकल जैन समाज के द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान कार्यक्रम होगा। दिनांक 31 मार्च को प्रातः 8.30 बजे तार बंगला दिगम्बर जैन मंदिर एवं जैन दिवाकर द्वार से सकल जैन समाज का विशाल चल समारोह निकाला जायेगा। यह चल समारोह हॉस्पिटल रोड, गांधी चौराहा, कालाखेत होते हुए सदर बाजार, उतारा धानमण्डी, जनकुपुरा मुख्य मार्ग (राजेन्द्र सूरी जैन शताब्दी मार्ग), अशोक टॉकीज रोड, वरूणदेव मंदिर चौक, नयापुरा रोड होते हुए माहेश्वरी भवन पहुंचेगा यहां सकल जैन समाज का स्वामीवात्सल्य होगा। सकल जैन समाज से आग्रह है कि वे इन दोनों दिवस कार्यक्रमों में शामिल होवे।

जब तक तमाशा न करो, सुनवाई नही होती

माही की गूंज, रतलाम।

मंगलवार दोपहर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान उस समय अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब शिवपुर निवासी अरुण शर्मा करीब 15 किलोमीटर दूर से घोड़ी पर सवार होकर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। अरुण शर्मा ने गोचर (चारागाह) भूमि एवं गांव के कांकड़ से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाने पर उन्होंने डिप्टी कलेक्टर संजय शर्मा को अपना आवेदन दिया।

बिना तमाशा किए कोई नहीं सुनता बात

आवेदन सौंपने के बाद वे वापस घोड़ी पर सवार होकर लौट गए। घोड़ी पर आने के सवाल पर शर्मा ने जवाब दिया कि आजकल हर किसी को तमाशा देखने का शौक है। बिना तमाशा किए कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए इस अंदाज में उन्हें आना पड़ा जिससे सबका ध्यान समस्या पर लाया जा सके।

चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से पशुओं का संकट

आवेदन में अरुण शर्मा ने बताया कि जिले के अधिकांश गांवों में पशु-पक्षियों और जीव-जंतुओं के लिए निर्धारित सरकारी चारागाह भूमि पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके चलते पशुओं के रहने की जगह समाप्त होती जा रही है और किसानों के लिए भी यह समस्या बनती जा रही है। वर्तमान हालात में पशुओं को कहीं ठहरने की जगह नहीं बची है। जानवरों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे जाएं तो कहां जाएं, रहें तो कहां रहें। कोई इधर से भगाता है तो कोई उधर से, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए लिखा।

जीव-जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा

आधे से अधिक पशु समाप्त हो चुके हैं और यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में जीव-जंतुओं का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। शर्मा ने चेतावनी देते हुए लिखा कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इसका दुष्परिणाम मानव समाज को भी भुगतना पड़ेगा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि जिले की समस्त चारागाह एवं कांकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, ताकि पशुओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

जिले की 205 ग्राम पंचायत टीबी से मुक्त

माही की गूंज, मंदसौर। जिले में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे आडिटोरियम में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले की 205 ग्राम पंचायतों को क्षय रोग (टीबी) से मुक्त घोषित करते हुए सरपंच, सचिवों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया।

कार्यक्रम में कलेक्टर अदिती गर्ग, विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, मेडिकल कॉलेज डीन, सीएमएचओ सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कलेक्टर अदिती गर्ग ने कहा कि जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयासों से मंदसौर जिले ने टीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने सभी के सहयोग को इस सफलता का आधार बताया।

विधायक विपिन जैन ने कहा कि 205 ग्राम पंचायतों का टीबी मुक्त होना जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि मरीजों को 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि के साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। मंदसौर जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

कार्यक्रम के दौरान टीबी मुक्ति संकल्प पत्र का विमोचन किया गया तथा उपस्थित सभी लोगों को टीबी मुक्त मंदसौर की शपथ दिलाई गई। अंत में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर एवं कलेक्टर द्वारा टीबी मुक्त भारत प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाह से पंपों पर उमड़ी भीड़

माही की गूंज, बड़वानी।

बुधवार सुबह पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सामाजिक माध्यमों पर ईंधन की कमी की अफवाहों से घबराकर लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां भरवाने पहुंच रहे हैं। मंगलवार रात से ही पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ने लगी थी, जो बुधवार सुबह तक जारी रही। कुछ ही देर में कई पंपों पर लंबी कतारें लग गईं, जिससे पंप संचालक भी हैरान रह गए। बाद में पता चला कि सामाजिक माध्यमों पर फैली अफवाहों ने लोगों को डरा दिया था।

दरअसल, पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर भ्रामक संदेश तेजी से प्रसारित हो रहे थे। इन संदेशों से घबराकर लोग एहतियातन अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवाने लगे। उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें सामाजिक माध्यमों के जरिए ही किल्लत की जानकारी मिली थी।

पेट्रोल पंप संचालक अजय पाटीदार ने आम नागरिकों से अनावश्यक खरीदारी न करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भंडार स्तर पर ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से आपूर्ति दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जमाखोरी की कोशिश करने वालों को ईंधन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आम उपभोक्ता और किसानों के लिए कोई समस्या नहीं है।

जिला आपूर्ति अधिकारी भरत सिंह जमरे ने बताया कि बड़वानी जिले में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार से घबराएं नहीं और अनावश्यक खरीदारी न करें। जिले में मांग के अनुसार आपूर्ति निरंतर जारी है। प्रशासन ने लोगों से अप्रमाणित सूचनाओं और अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है।

पंप संचालकों ने स्पष्ट किया कि शहर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि यह स्थिति पूरी तरह अनावश्यक खरीदारी के कारण बनी है।

सामाजिक माध्यमों पर पेट्रोल-डीजल की कमी की खबरें तेजी से फैलने लगीं और लोगों में घबराहट बढ़ गई। इसी डर के चलते लोग अपने-अपने वाहनों के साथ पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। हर जगह लंबी कतारें लग गईं और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया।

पंप संचालकों के अनुसार उनके पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद था। पुलिस पंप पर करीब हजार लीटर डीजल और हजार लीटर पेट्रोल उपलब्ध था, वहीं अन्य पंपों पर भी संपीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी थी।

दरअसल, तेल कंपनियों ने उधारी पर ईंधन देना फिलहाल बंद कर दिया था और अग्रिम भुगतान पर ही आपूर्ति हो रही थी। इसी कारण कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे अफवाह फैल गई और शहर में अचानक भीड़ उमड़ पड़ी।

पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मी की पिटाई

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले में पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाह के बाद पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जिला मुख्यालय के कई पंपों पर 'पेट्रोल-डीजल समाप्त' होने के सूचना पत्र चस्पा कर दिए गए हैं। इस बीच, बुधवार को जुलवानिया में एक पेट्रोल पंप पर लाइन में लगने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने पुलिस आरक्षक पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया।

घायल आरक्षक अखिलेश चौहान ने बताया कि पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ के कारण पुलिस की सुरक्षा में ईंधन का वितरण किया जा रहा था। इसी दौरान एक युवक ने लाइन में लगने की बात पर पेट्रोल टंकी का ढक्कन फेंककर उन पर हमला कर दिया। आरक्षक के मुंह और छाती पर चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जुलवानिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घटना का सीसीटीवी दृश्य भी सामने आया है, जिसके आधार पर हमलावर युवक की पहचान की जा रही है।

जुलवानिया सहित जिले के कई पेट्रोल पंपों पर मंगलवार आधी रात से लेकर बुधवार सुबह तक भीड़ लगातार बनी रही, जिससे कई स्थानों पर ईंधन समाप्त हो गया। घंटों इंतजार के बाद भी पेट्रोल न मिलने पर लोग खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। शहर में कलेक्टर आवास के सामने स्थित पुलिस पेट्रोल पंप और बाईपास के दो अन्य पंपों पर भी पेट्रोल और डीजल दोनों समाप्त होने के बोर्ड लगे मिले।

जिन पेट्रोल पंपों पर अभी भी ईंधन उपलब्ध है, वहां लोग ड्रम, डिब्बों और बोतलों में पेट्रोल-डीजल भरकर संग्रह करते देखे जा रहे हैं। यह स्थिति रसोई गैस सिलेंडर के लिए लगने वाली लंबी लाइनों के समान हो गई है।

किसान संघ ने ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने की मांग की

माही की गूंज, खंडवा।

भारतीय किसान संघ की जिला प्रशासन के साथ बुधवार को जिला पंचायत सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आगामी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले गेहूं एवं चना उपार्जन को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में अपर कलेक्टर केआर बडोले, सृष्टि देशमुख व उप संचालक कृषि नितेश यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। किसान संघ के पदाधिकारियों ने उपार्जन प्रक्रिया में आने वाली संभावित समस्याओं और उनके समाधान को लेकर प्रशासन के सामने अपने सुझाव रखे। संघ ने बताया कि इस वर्ष गेहूं और चने की फसल उच्च गुणवत्ता की हुई है, इसलिए किसानों को ÷मिट्टी कुसी÷ जैसे कारण बताकर अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।

साथ ही सभी उपार्जन केंद्रों पर बिजली, पानी और छांव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। किसानों ने यह भी सुझाव दिया कि बड़े प्लेट कांटों पर ट्रॉलियों से सीधे उपज की तौल की व्यवस्था की जाए, ताकि प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन सके। बैठक में एक अहम मुद्दा ऋण वसूली की तिथि को लेकर भी उठा।

किसान संघ ने शासन को अवगत कराया कि जब खरीदी 1 अप्रैल से शुरू हो रही है, तो 28 मार्च को ऋण वसूली की तिथि रखना किसानों के लिए परेशानी का कारण है। संघ ने ज्ञापन सौंपकर मांग की कि बैंकों द्वारा ऋण वसूली की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तक बढ़ाई जाए।

उप संचालक कृषि नितेश यादव ने आगामी सत्र में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर टोकन प्रणाली पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रक्षेपक के माध्यम से किसानों को खाद बुकिंग की प्रक्रिया भी समझाई।

बैठक में भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष राधेश्याम चाचरिया, जिला मंत्री सुभाष पटेल, अभिषेक गंगराड़े सहित संदीप सिंह सोलंकी, रामेश्वर कुशवाहा, दिनेश महाजन, शैलेंद्र सिंह, गुलाब, सेवकराम, ताराचंद, हरसिंह डोडे और राकेश सिंह समेत कई किसान उपस्थित रहे।

खेत में लगी आग, 3 एकड़ फसल खाक

माही की गूंज, बड़वानी।

कुंदन नगर स्थित गोरीधाम कॉलोनी के पास एक खेत में भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 3 एकड़ में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण विद्युत लाइन में खराबी बताया जा रहा है।

प्रभावित किसानों में मोहन अगलचा और सेंगवा निवासी अनिल शामिल हैं। किसान संतोष ने आरोप लगाया कि यह घटना विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण हुई है। उनके अनुसार, खेतों में कई जगह तार ढीले और खुले पड़े हैं, जिनकी समय पर मरम्मत नहीं की जाती।

अनिल ने बताया कि उनकी लगभग 3 एकड़ की फसल जल गई, जिससे उन्हें तीन लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने भी विद्युत मंडल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यदि समय पर लाइन सुधार कार्य होता, तो यह नुकसान टाला जा सकता था।

आग लगने की सूचना मिलते ही नगर पालिका की अग्निशमन गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे इसे अन्य खेतों में फैलने से रोका जा सका।

फिलहाल, नुकसान के आकलन के लिए सर्वेक्षण दल का इंतजार किया जा रहा है। किसानों ने पटवारी से संपर्क किया है, जिन्होंने जल्द मौके पर पहुंचने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र सर्वेक्षण कर उचित मुआवजा देने और विद्युत व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

बच्चे पर तेंदुए का हमला, पांच ग्रामीण घायल

माही की गूंज, बड़वानी।

जूनापानी गांव में बुधवार सुबह एक तेंदुए ने खेत में पानी दे रहे एक बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे को बचाने के लिए ग्रामीण लाठियां लेकर तेंदुए से भिड़ गए। इस दौरान पांच ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि तेंदुए की भी मौत हो गई।

गांव के नंदू ठाकुर ने बताया कि उनका बेटा जीवन खेत में पानी देने गया था। उसी समय वे भी सूखी मक्का काटने के लिए खेत की ओर जा रहे थे। तभी जंगल से आए तेंदुए ने उनके बेटे पर हमला कर दिया। यह देखकर उन्होंने बेटे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेंदुए ने उन पर भी हमला कर दिया।

करीब आधे मिनट तक उनका तेंदुए से संघर्ष चलता रहा। उन्होंने तेंदुए की गर्दन पकड़ ली थी, जबकि तेंदुए ने उनका हाथ मुंह में दबोच लिया था। कुछ देर बाद तेंदुआ वहां से भाग गया और उसने तीन अन्य ग्रामीणों पर भी हमला कर दिया, जिससे वे भी घायल हो गए। तेंदुए के हमले में पिता-पुत्र सहित पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों को वरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सेंधवा रेफर किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना कई बार वन विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने यह भी आशंका जताई है कि इलाके में एक और तेंदुआ मौजूद है, जिससे खतरा बना हुआ है।

ये हुए घायल जीवन पिता नंदू 28 वर्ष, नंदू पिता गाना 45 वर्ष, कल्याण सिंह पिता अदा 52 वर्ष, चिंटू पिता लाल सिंह 32 वर्ष, सुरेश पिता निम्बा 28 वर्ष वन विभाग के डीएफओ आईएस गड़रिया ने बताया कि जूनापानी क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधि की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी और खोज के निर्देश दिए गए थे। बुधवार सुबह सूचना मिली कि तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला किया है।

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां तेंदुआ घायल अवस्था में मिला। उसे उपचार के लिए वरला ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तेंदुए का पशु चिकित्सक द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी और वन विभाग के अधिकारी मुकेश मरावी मौके पर पहुंचे। विधायक ने घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल क्षेत्र में न जाने और वन्य प्राणियों से सतर्क रहने की अपील की है।

संतुलन के लिए जरूरी रणनीतिक दिशा तय करना

गुरबचन जगत

जून, 1914 में ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांज़ फर्डिनेंड की हत्या उन मुख्य घटनाओं में से एक मानी जाती है जिनके परिणाम में प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में अंतर्निहित बड़ा कारण था कि 'केंद्रीय शक्तियां' (जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और ओटोमन साम्राज्य) दुनियाभर में साम्राज्यवादी विस्तार और औपनिवेशीकरण करने की दौड़ में देर से शामिल हुईं, जिसमें ब्रिटेन व फ्रांस वर्चस्व कायम कर चुके थे।

कैसर विल्हेम द्वितीय के नेतृत्व में जर्मनी ने साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा पाली थी,और इसी के चलते तनाव-संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। बाकी सब इतिहास है। चार साल (1914-18) चले युद्ध में सैन्य व नागरिक हताहतों की संख्या 1.5 से 2.2 करोड़ होने का अनुमान है। वर्साय संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध औपचारिक रूप से खत्म हो पाया। लेकिन दुखद, इंसान की स्मृति इतनी कमज़ोर कि शायद ही कोई साल गुज़रता हो जब विश्व में कहं न कहीं हिंसा न भड़कती हो।

व्यक्तियों की तरह, गरीब देश भी आपस में नहीं लड़ते-सिवाय कुछ मामलों के जहां विकास अभी कबीलाई चरण में है। अमीर, विकसित और सैन्य रूप से शक्तिशाली देश ही परस्पर लड़ते हैं, या फिर गरीब लेकिन प्राकृतिक संसाधन समृद्ध राष्ट्रों को उपनिवेश बनाने की कोशिश करते हैं। धर्म व नस्ल की इसमें अहम भूमिका हैं-अमूमन छद्म रूप में। किसी इंसान या देश को आखिर कितनी ज़मीन चाहिए? क्या यह कभी काफी रही? या फिर यह कि आप जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं, लालसी उतनी ही बढ़ती जाती है?

प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी, जापान और इटली ('धुरी की शक्तियां') अपने विशाल संसाधन के बूते धीरे-धीरे शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में उभरे; लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, प्रशांत द्वीपों और एशिया को जीतने का प्रयास किया। शक्तिशाली देशों को सदा प्रगति की ज़रूरत रहती है; यथास्थिति कभी पर्याप्त नहीं रही। उन्हें और भूमि व संसाधन चाहिए होते हैं, लूटने के लिए और धन व गुलाम बनाने को और अधिक स्त्री-पुरुष चाहिए होते हैं। इसी कारण द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया, जिसमें करोड़ों जानें गई और शहर और देश तबाह हुए। द्वितीयविश्व युद्ध में हुआ नुकसान प्रथम विश्वयुद्ध के मुकाबले कहीं अधिक था।

आज दौड़ दुर्लभ भू-खनिजों, आपूर्ति शृंखलाओं और इनके खनन, प्रसंस्करण से चुंबक बनाने की पूरी मूल्य शृंखला को सुरक्षित करने की लगी है। अमेरिका और चीन जैसी विशाल अर्थव्यवस्थाओं को इनकी ज़रूरत है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें अपने बड़े-बड़े डेटा सेंटर चलाने के लिए बेतहाशा ऊर्जा चाहिये। चूंकि हर चीज़ को जीडीपी वृद्धि के रूप में आंका जाता है, इसलिए कंपनियों के लिए ग्रोथ ज़रूरी है और मुकाबला बहुत कड़ा, गलाकाट है। निजी उद्योग से शुरू हुआ यह मामला धीरे-धीरे सियासी अखाड़े में फैल जाता है और जल्द ही सेनाएं भी आकर शामिल हो जाती हैं।

कटिंग ऑफ द चाईनीज़ मेलन' (चीन को कब्जाने की तत्कालीन औपनिवेशिक ताकतों में होड़) से लेकर 'स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका'(अफ्रीकी देशों को गुलाम बनाने की दौड़) तक, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब बड़ी ताकतों ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने को कमज़ोर देशों की अर्थव्यवस्थाओं और संसाधनों को आपस में बांट लिया। रूस, जिसके पास असीम भूमि है, यूक्रेन को पाना चाहता हैकृजिसे उसने सोवियत संघ के विघटन के साथ खो दिया था। यूक्रेन अपने मानव संसाधन, ज़मीन, परमाणु स्रोत और समुद्र तक पहुंच मार्ग के मामले में बहुत समृद्ध है, और रूस इसे पाना चाहता है। हमला करने का मौका तब मिला जब आशंका फलीभूत हुई कि नाटो यूक्रेन के जरिए रूस बॉर्डर तक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। नाटो को भी यूक्रेन में वैसा ही मौका दिखा और वह भी उसके संसाधनों को बांटना चाहता है, जिसमें अमेरिकी स्पष्ट रूप से युद्ध का हर्जाना मांग रहा है। तरीका व परिणाम वही पुराना, युद्ध का तांडव।

वेनेज़ुएला, अपने विशाल तेल भंडारों के साथ, अमेरिका के लिए आसान शिकार रहा। क्यूबा और ग्रीनलैंड अब सूची में अगले क्रम में हैं। वहीं इस्राइल मध्य-पूर्व को मर्ज़ी मुताबिक ढालना चाहता है, वहीं ईरान की अपनी योजना है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर पूर्व-हमला कर दिया था, वैसे ही अमेरिकियों-इस्राइलियों ने ईरान को न्यूक्लियर बम और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण से रोकने को उस पर वार किया।

तेल समृद्ध खाड़ी देश सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं और इसलिए नुकसान झेल रहे हैं, वैसे ही जैसे ईरान की अप्रत्याशित युद्ध नीति व प्रतिक्रिया के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था हानि झेल रही है। बीते जमाने में, युद्ध थमने के बाद संधियों और संगठनों के जरिये आशा की किरण जगी- बतौर लीग ऑफ नेशन्स के उत्तराधिकारी राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा यकीनी बनाए रखने के उद्देश्य से हुई; द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में मदद के लिए विश्व बैंक समूह (पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक) की स्थापना की गई; व्यापार में अड़चनें कम करने को विश्व व्यापार संगठन (मूलतः जीएटीटी, टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य संधि) बनाया; अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया; विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य का समन्वय था; लंबी सूची में यूनिसेफ, यूनेस्को, आदि कई संगठन, संस्थान हैं, जिनके जरिये तत्कालीन नेतृत्व ने अतीत की गलतियां व भूलें सुधारने का प्रयास किया।

इस घटनाक्रम में महान नेतृत्व भी पाया- हैरी एस. ट्रूमैन ने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान लागू किया और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका का नेतृत्व किया। ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल ने न केवल युद्ध के दौरान नेतृत्व किया, बल्कि युद्धोत्तर व्यवस्था के गठन में अहम भूमिका निभाई, जिसमें उनके द्वारा गढ़ा 'आयरन् कर्टेन' विशेषण भी शामिल है। चार्ल्स डी गॉल ने पांचवें गणराज्य की स्थापना की और फ्रांस को एक पराजित राष्ट्र से यूरोप की मुख्य शक्ति में बदला। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने में नेतृत्व किया,वहीं युद्धोत्तर पुनर्निर्माण व पूर्वी धड़े की स्थापना में योगदान दिया। उनकी राजनीतिक विचारधाराएं भिन्न थीं, लेकिन वे अपने-अपने देशों के महान नेता थे। आज, लगता है कि दुनिया 20वीं सदी के आरंभिक दौर में लौट गई है, जहां नेता दूसरे देशों को 'हड़पने' और 'नष्ट करने' की बातें कर रहे हैं-हमारे समय का नैतिक मार्गदर्शन कहां गया? उपरोक्त अधिकांश संगठनों को कमजोर होने दिया गया और आज वे अपने पूर्व स्वरूप का ढांचा व परछाई मात्र हैं। अमेरिका पूर्ण वर्चस्व दिखा रहा और सदियों पुराने नाटो सहयोगियों तक को मान्यता से इनकार कर रहा है।

वैश्विक व्यापार समझौते बीते जमाने की बात हो गए, क्योंकि अमेरिका एकतरफा टैरिफ लगा रहा और अलग-अलग देश अस्तित्व की खातिर व्यापारिक गठबंधन बना रहे हैं। चीन और रूस अपनी अलग धुन पर चल रहे और दुनिया के हिस्से हथिया रहे हैं। फिर तकनीक विशेषज्ञ विशाल कंपनियों के बड़े-बड़े धन्ना सेठ हैं जिनके पास निजी सोच लागू करने के लिए अकल्पनीय पैसा और संसाधन हैं... सत्ता चंद लोगों के हाथों में सिमट गई, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसा कि लॉर्ड एक्टन ने कहा था, 'सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है'। एपस्टीन फाइलों में नामों की सूची नैतिक पतन दर्शाती है। देशों के बीच फिर संतुलन स्थापना की ज़रूरत है।

जैसे-जैसे बड़ी ताकतें अपने खेल खेलेंगी, वे दूसरे देशों को भी युद्ध के भंवर में खींच लेंगी। समय आ गया कि हम पुराने सहयोगियों को ध्यान में रख अपनी रणनीतिक दिशा तय करें और देशदेश को सुरक्षित रखने को नए गठबंधन भी बनाएं। भारत ने सदा अंतर्राष्ट्रीय राय व दिशा तय करने में क्षमता से कहीं ज़्यादा जाकर भूमिका निभाई। आज, हमें संतुलन स्थापना की अपनी पुरानी आवाज़ और नैतिक ईमानदारी ढूंढ़नी होगी, सुनिश्चित करना होगा कि यह देश के अंदर और विदेशी संबंधों, दोनों में ही गूंजे।मुश्किलों भरे मौजूदा समय से पार पाने को यह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय संघर्ष और युद्ध के चलते हमारी अर्थव्यवस्था और आंतरिक-बाह्य सुरक्षा, दोनों पर ही खतरा मंडरा रहा है।

गैस संकट पर उद्योगों को मिला भरोसा

माही की गूंज, उज्जैन।

खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बीच देशभर में गैस संकट जैसे हालात बन रहे हैं। उद्योगों को गैस की कमी न आए और औद्योगिक उत्पादन बाधित न हो, इसको लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एमपीआईडीसी में उद्योगपतियों की अहम बैठक हुई।

बैठक में उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया गया कि मौजूदा स्थिति भले चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हालात में सुधार के लिए सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर बेहतर समाधान की दिशा में काम कर रही हैं। सप्लाई व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही हालात बेहतर होंगे।

एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौड़ ने कहा कि कोरोना काल की तरह यह भी एक आपातकाल जैसी स्थिति है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। शासन, प्रशासन और गैस कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, ताकि उद्योगों पर इसका कम से कम असर आए। उद्यमियों से भी सहयोग की अपील की और कहा कि किसी भी तरह की समस्या होने पर तत्काल इसकी जानकारी दें, ताकि उसका त्वरित समाधान किया जा सके। साथ ही उद्योग प्रतिनिधियों से ईंधन का वैकल्पिक साधन अपनाने एवं उपलब्धता अनुसार पीएनजी कनेक्शन लेने की समझाइश दी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश को उपलब्ध गैस कोटे में से 5 प्रतिशत हिस्सा उद्योगों के लिए आरक्षित किया है, जिससे उद्योगों में गैस की कमी से निपटने में काफी हद तक मदद मिलेगी और उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। पीएनजी सप्लाई को और बेहतर बनाने के लिए गुजरात गैस कंपनी द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। फैक्टरियों तक पीएनजी की लाइन डल चुकी है और जल्द ही सप्लाई शुरू हो जाएगी।

सहायक वितरण अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि उद्योगों की जरूरत के अनुसार गैस देने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधयों से उनकी वास्तविक मांग भेजने को कहा, ताकि सप्लाई का बेहतर प्रबंधन किया जा सके और किसी भी तरह की कमी की स्थिति न बने। साथ ही फैक्टरियों में चल रही कैंटीन में व्यावसायिक सिलेंडर की वास्तविक खपत की सप्लाई भी निर्बाध जारी रखने का भरोसा दिलाया।

गैस सप्लाई शेड्यूल बेहतर हो, नियमों में छूट मिलेउद्योगपतियों ने गैस सप्लाई में अनिश्चितता को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि सीमित गैस मिलने से उत्पादन सीधे प्रभावित हो सकता है और यूनिट्स को आधी क्षमता पर काम करना पड़ सकता है। इससे न सिर्फ ऑर्डर पूरे करने में दिक्कत आ सकती है, बल्कि लागत भी बढ़ सकती है। उन्होंने गैस सप्लाई का शेड्यूल और स्पष्ट करने और जंबो गैस कनेक्शन को लेकर नियमों में छूट देने और अतिरिक्त गैस उपयोग पर लगने वाले भारी शुल्क को कम करने का सुझाव दिया। साथ ही सरकार से टैक्स में राहत और लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के उपाय करने की मांग की। पीएनजी सप्लाई नेटवर्क को और मजबूत करने और दबाव (प्रेशर) की समस्या दूर करने की भी बात रखी।

यह अस्थायी स्थिति है

राठौड़एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौड़ के अनुसार मौजूदा स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक अस्थायी स्थिति है, जिसे सरकार, प्रशासन और गैस कंपनियां मिलकर संभाल रही हैं। उद्योगों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जहां भी समस्या आ रही है, उसका प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है और सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम जारी है।

पुलिस ने जप्त की अवैध शराब

माही की गूंज, चं.शे. आजादनगर।

थाना आजादनगर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। एक सफेद रंग की हुण्डई औरा कार (क्रमांक जीजे 20 सीए 2213) में अवैध मदिरा भरकर कालीयावाव मार्ग से दाहोद (गुजरात) की ओर ले जाई जा रही है। प्राप्त सूचना पर थाना प्रभारी आजादनगर निरीक्षक शिवराम तरोले के नेतृत्व मे गठित टीम के वाहन की घेराबंदी हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा ग्राम कालीयावाव स्थित हथनी नदी पुलिया के समीप नाकाबंदी कर आने-जाने वालें संदिग्ध वाहन के आने पर उसे रोककर तलाशी की कार्यवाही की गई। जिसस पर एक कार की पिछली सीट और डिक्की में बडी मात्रा में अवैध शराब पाई गई। वाहन में सवार व्यक्तियों ने अपना नाम जयश पिता राजेश तडवी (उम्र 20 वर्ष) तथा चेतन पिता सुरदास भाई रावत (उम्र 20 वर्ष), दोनों निवासी जिला दाहोद (गुजरात) बताया।

उक्त कार्रवाई में बियर की 15 पेटी के साथ वाहन को भी जप्त किया गया। शराब के परिवहन के संबंध में आरोपियों द्वारा कोई वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर, थाना आजादनगर में अपराध क्रमांक 103/2026, धारा 34(2), 46 आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक शिवराम तरोले, सउनि दिनेश नरगावे, सउनि भूपेन्द्र नायक, प्रआर जवसिंह, आरक्षक बबलू, राकेश, विजय, रणसिंह एवं तूफान का योगदान रहा है।

टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ

माही की गूंज, आलीराजपुर।

विश्व टीबी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 100 दिवसीय ÷टीबी मुक्त भारत अभियान÷ का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के मार्गदर्शन में प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर की गई।

इस दौरान कलेक्टर श्रीमती माथुर ने अभियान को सफल बनाने हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने टीबी के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और समय पर जांच व उपचार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती माथुर द्वारा 5 टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरित किए गए साथ ही निर्देश दिए गए कि जिले के सभी टीबी मरीजों को शत-प्रतिशत उपचार एवं पोषण सहायता उपलब्ध कराई जाए। शुभारंभ अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश अतुलकर, जिला क्षय अधिकारी सहित समस्त टीबी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भीड़

माही की गूंज, आम्बुआ।

अमेरिका इजरायल की इराक के साथ चल रहे भीषण युद्ध का असर भारत के ह्रदय प्रदेश मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल समाप्त होने तथा पेट्रोल नहीं मिलेगा कि अफवाह के कारण आम्बुआ में भी बुधवार दोपहर से समाचार लिखे जाने तक दो पहिया वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। जिला प्रशासन की अपील के बाबजूद लोग समझने को तैयार नहीं है पेट्रोल पंपों संचालक तथा कर्मचारी परेशान हैं।

समाचार लिखे जाने तक पता चला है कि आम्बुआ स्थिति दो पेट्रोल पंपों तथा समीप ग्राम बोरझाड में एक पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल समाप्त हो जाने के कारण बंद करना पड़ा है तथा पेट्रोल डीजल आने के बाद पुनः चालू हो सकेंगे। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कंपनियों द्वारा डीलरों को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधा बंद कर दी गई है तथा अब केश पेमेंट बैंकों के माध्यम से खातों में भुक्तान जमा कराने के बाद डीज़ल व पेट्रोल टेंकर भेजे जाना है।

शादी विवाह के मद्देनजर दुकानों पर ग्राहकों की भीड़

माही की गूंज, आम्बुआ।

आगामी दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह उत्सव की धूम धाम होने वाली है, जिसके लिए ग्रामीण विशेष कर महिलाओं की भीड़ इन दिनों बाजार में देखी जा सकती है। क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति पर्व भगोरिया तथा होलिका दहन के बाद सातम एवं गणगौर समाप्ति के चैत्र नवरात्र भी समाप्ति पर है। अब क्षेत्र में विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह के कार्यक्रम प्रारंभ होंगें। जिनकी तैयारी में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लोग विशेष रूप से महिलाएं सक्रिय दिखाई देने लगी है। आम्बुआ में साप्ताहिक हाट बाजार में खरीदारी करने उमड़ी भीड़ को देखकर यही कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में बाजार गुलजार रहेंगे। देखा जा सकता है कि महिला खरीदारी करने हेतु कपड़ों की दकानों पर अधिक आ रही है अधिकतर अपना अपना ग्रूप बना कर एक जैसा परिधान चुन रही है तथा किसी एक कपड़ा सिलने वाले दर्जी के यहां कपड़े सिलाए जा रहे हैं। एक रंग के घाघरे के साथ वैसा ही ब्लाउज तथा साड़ी या लुगड़ा (ओढ़नी) खरीदी जा रही है यही ग्रूप शादियों में एक आदिवासी संस्कृति के लोकनृत्य ढोल मांदल तथा डी जे की धुन पर करके अलग छटा बिखेरेंगी।

नहीं पहुंचे मंत्री तो बेटा ही बन गया चीफ गेस्ट

भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड ज़िले में हुए एक सरकारी कार्यक्रम पर विवाद खड़ा हो गया है। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला को बतौर मुख्य अतिथि आना था लेकिन जब वो नहीं आए तो उनके बेटे को चीफ गेस्ट बनाकर कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस ने अब इसपर सवाल खड़े किए हैं और राज्य सरकार पर हमला बोला है।

दरअसल, भिंड ज़िले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में 'संकल्प से समाधान' कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी थी। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला को कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उनकी जगह उनके बेटे आलोक शुक्ला कार्यक्रम में पहुंचे हैरानी की बात यह रही कि अधिकारियों ने उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर स्थान दिया और उनके हाथों से ही हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बंटवा दिए।

कांग्रेस बोली, कल को बेटे को भेजेंगे कैबिनेट बैठक में?

हैरानी की बात यह है कि आलोक शुक्ला किसी वैधानिक पद पर नहीं हैं इसके बावजूद उनके लिए पूरा प्रोटोकॉल रहा। अब कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि, अफसरों ने बीजेपी नेताओं को खुश करने के लिए नियम कायदे ताक पर रखा दिए हैं। यह कौन सा नियम है कि मंत्री नहीं आए तो बेटे को चीफ गेस्ट बना दो...? इस हिसाब से तो कल को मंत्री अपनी जगह बेटे को कैबिनेट बैठक में भेजना शुरू कर देंगे...?

वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर सीईओ जिला पंचायत वीर सिंह चौहान ने कहा कि, मंत्री को कार्यक्रम में आना था, लेकिन वे नहीं आ पाए। उनके प्रतिनिधि के रूप में बेटे आए इसलिए उनसे प्रमाण पत्र वितरण कराया गया।

उज्जैन विकास प्राधिकरण ने ढहाए 9 अवैध अतिक्रमण

माही की गूंज, उज्जैन। शहर में शहर विकास प्राधिकरण ने हरिफाटक आवासीय योजनान्तर्गत 9 अवैध अतिक्रमण हटाए। ये भूखण्ड क्रं.231 ए,66 एवं 66 ए व उसके तीन भाग 67 ए एवं बी,68बी,69 ए एवं बी, 71,72,73 एवं 74 पर निर्मित अवैध निर्माणों को ढहाया।इस कार्यवाही से हरिफाटक मार्ग चौड़ीकरण एवं हरिफाटक ओव्हरब्रिज कार्य को गति मिलेगी। उविप्रा सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि, उक्त भूखण्ड 40 से 45 वर्ष पूर्व आवासीय उद्देश्य से लीज पर दिए गए थे। कई रहवासियों ने लीज डीड का उल्लंघन करते हुए रहवासी की जगह इनका व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया था। ऐसा करना,बिना उविप्रा की अनुमति से विक्रय करना और भूखण्डों का विभाजन करना शर्तो का उल्लंघन था। इसीलिए लीज निरस्ती पश्चात इन्हें हटाया गया। इसके पूर्व 23 भूखण्डों पर बने अवैधानिक भवनों को तोड़ा जा चुका है। मंगलवार को इस कार्य में जिला प्रशासन,पुलिस विभाग एवं नगर निगम का सहयोग मिला। इस कार्यवाही में 2 पोकलेन, 6 जेसीबी, 50 कर्मचारियों की गैंग तथा 100 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी शामिल रहे।

जिले में पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता

माही की गूंज, आलीराजपुर।

जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के निर्देशानुसार राजस्व अधिकारियों द्वारा विभिन्न पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर स्टॉक का सत्यापन किया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित हो रही है।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और पेनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) से बचें। पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वाहन चालकों को केवल आवश्यकता अनुसार ही ईंधन उपलब्ध कराया जाए तथा अवैध रूप से बिक्री और भंडारण करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के तहत अनुविभागीय अधिकारी जोबट वीरेंद्र बघेल उदयगढ़ पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया। वहीं डिप्टी कलेक्टर सुश्री दीपिका पाटीदार ने जोबट क्षेत्र के पेट्रोल पंपों का जायजा लिया। नायब तहसीलदार सुश्री सरिता बालेचा ने सोरवा एवं चांदपुर स्थित पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर स्टॉक और व्यवस्थाओं की जांच की। इसी प्रकार जिले के सभी राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर स्टॉक एवं वितरण व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया गया।

2027 के आर्मी परेड की मेजबानी करेगा मध्यप्रदेश

भोपाल।

मध्य प्रदेश के इतिहास में 15 जनवरी 2027 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ बैठक के बाद ऐलान किया कि 2027 का राष्ट्रीय सेना दिवस समारोह भोपाल में आयोजित किया जाएगा। दरअसल, सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में जनरल सर एफआरआर बुचर से सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ के तौर पर केएम करिअप्पा के पदभार संभालने की याद में मनाया जाता है।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सीएम यादव ने कहा कि यह भव्य समारोह राज्य के नागरिकों को देश की समृद्ध सैन्य विरासत से परिचित कराएगा और युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। यादव ने कहा, ÷प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने हर मौके पर अदम्य साहस, वीरता और शक्ति का प्रदर्शन किया है। राज्य के नागरिकों को सेना की समृद्ध सैन्य विरासत से परिचित कराने और राज्य के युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 जनवरी 2027 को भोपाल में एक विशेष परेड आयोजित की जाएगी।÷

मुख्यमंत्री ने कहा कि, भोपाल में इन सेना दिवस कार्यक्रमों में शामिल होने का अनुभव 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों जैसा ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार इन कार्यक्रमों के लिए सेना को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

सीएम यादव ने कहा, ÷इस अवसर पर सेना 'शौर्य संध्या' का आयोजन करेगी। इसमें सेना के हथियारों, संसाधनों और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, साथ ही सैन्य अभ्यासों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस मौके पर रिटायर्ड सैनिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। सभी गतिविधियां उसी भव्यता और गरिमा के साथ आयोजित की जाएंगी, जैसी 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देखने को मिलती हैं।÷

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इन समारोहों में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को सैन्य परेड से जोड़ना है, साथ ही सेना और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना भी है।

1 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा उत्सव

15 जनवरी को होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी कुछ गतिविधियां 1 नवंबर से ही शुरू हो जाएंगी। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 'मेरी माटी' अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों से मिट्टी लाई जाएगी। भोपाल स्थित 'शौर्य स्मारक' में एक 'संकल्प वृक्ष' लगाया जाएगा।÷

क्यों मनाया जाता है सेना दिवस...?

बता दें कि, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को विकेंद्रीकृत करने की पहल 2023 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के विजन को मबूत करना और भारतीय सेना में देशव्यापी जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना था, साथ ही सेना और नागरिकों के बीच संबंधों को भी मजबूत करना था।

गैस, पेट्रोल-डीजल किल्लत की हकीकत क्या है...?

प्रशासन कर रहा गुहार, जनता रही नकार...

माही की गूंज, झाबुआ।

खाड़ी देशों में बनी युद्ध की गंभीर स्थिति के बीच भारत में सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर गर्म होता जा रहा हैं। देश में कई तरह की अफवाहें फैल रही है। इनमें ईंधन खत्म हो जाने जैसी अफवाहें प्रमुख है। इसको लेकर केंद्र सरकार के रेल व सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी बात रखते हुए बताया कि, देश की सभी रिफायनरी उच्च क्षमता से काम कर रही है। इससे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अफवाहों ने मध्यप्रदेश में हाहाकार मचाकर रख दिया है। पेट्रोल-डीजल खत्म होने की इस अफवाह से प्रदेश के झाबुआ, आलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास जैसे शहरों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। इन सभी जगहों पर लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर डीजल या पेट्रोल भरवाने के लिए मंगलवार को भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

स्थिति यह हो गई कि, प्रदेश के इन जिलों में पेट्रोल पंपों से एक ही दिन में तीन गुना से ज्यादा उठाव हो गया। हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल बिक गया। सभी पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिली। तो वहीं कुछ जगहों पर हालात इतने गंभीर देखे गए कि, पंप संचालकों से लोगों ने तू-तू, मैं-मैं और हुज्जत शुरू कर दी। नतीजा यह निकल कर सामने आया कि, ऐसी जगहों पर प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। आगे से जानकारी जुटाते हुए प्रशासनिक अमले ने लोगों से गुहार लगाना भी शुरू किया। अधिकारियों ने सोशल मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की कि, अफवाहों पर ध्यान देकर उत्तेजित ना हों कहीं भी किसी तरह की पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं हुई है। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडारण है और आने वाले एक-दो दिनों में आपुर्ति में स्थिति पूरी तरह कंट्रोल कर ली जाएगी। प्रशासनिक तंत्र की इस अपील के बाद थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली है।

मंगलवार को झाबुआ जिला मुख्यालय पर भी यही स्थिति बनी रही। लोग अफवाहों में आकर पेट्रोल पंपों तक पहुंचने लगे और देखते ही देखते शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें पेट्रोल-डीजल भरवाने को लेकर लग गई। पंप संचालकों के अनुसार पेट्रोल-डीजल को लेकर कोई कमी नहीं है। पर्याप्त भंडारण भी है। लोग अफवाहों में आकर बेवजह की भीड़ लगा रहे है। पेट्रोल पंपों पर लगने वाली

इस भीड़ के कारण पेट्रोल-डीजल की बिक्री में भारी उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल पंपों पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए जिला मुख्यालय के कुछेक पेट्रोल पंपों पर संचालकों द्वारा पेट्रोल-डीजल देने की सीमा तय कर दी गई। जिसमें दो पहियां वाहनों को 200 रूपए से अधिक का पेट्रोल नहीं दिया गया और चार पहियां वाहनों में 1000 रूपए से अधिक का डीजल नहीं भरा गया। यह स्थिति देखते हुए लोग और ज्यादा बेचैन हो गए। फिलहाल सरकार व तंत्र का यह दावा है कि, पेट्रोल और डीजल आपुर्ति को लेकर कोई संकट नहीं है। झाबुआ जिला प्रशासन व आपुर्ति अधिकारी ने स्थिति को देखते हुए सोशल मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से यह अपील की कि, अफवाहों में न आए, जिले में पेट्रोल और डीजल को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अफवाहों के चलते मंगलवार का दिन जिला मुख्यालय पर उथल-पुथल भरा रहा। बुधवार को जिला मुख्यालय के सभी पेट्रोल पंपों पर सामान्य स्थिति देखने को मिली, लेकिन बुधवार को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाह का असर देखने को मिला। अफवाह फैलती हुई अब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। इन्ही अफवाहों के चलते जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों पर बुधवार को भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएगी। लोगों में प्रशासन की अपील का असर धीरे-धीरे जरूर होगा। पंप संचालकों के अुनसार सप्लाई में अस्थायी तौर पर कुछ बाधाएं आई थी लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है। कुछ कंपनियों की सप्लाई में थोड़ा समय के लिए देरी हुई थी, जिसके कारण कुछ पंपों पर स्टॉक खत्म हो गया। हालांकि अब सप्लाई फिर से सामान्य हो रही है जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।

खवासा व बामनिया पेट्रोल पम्प के संचालक दिनेश मांण्डोत ने माही की गूंज को बताया कि, बुधवार को हमारे पम्पो पर भी अफवाहो के चलते डिजल-पेट्रोल भराने हेतु वाहनो की बड़ी कतार लग गई जिसमें 15 हजार लिटर डिजल स्टाक में था वह खत्म हो गया। माण्डोत ने बताया कि, हमें डिपो से पर्याप्त डिजल-पेट्रोल मिल रहा है, आमजन अफवाहो का शिकार न हो।

एलपीजी गैस की किल्लत देखने को मिल रही

वहीं दूसरी ओर जिले में गैस सिलेंडर को लेकर भी काफी उथल-पुथल वाली स्थिति देखने को मिल रही है। थोक उपभोक्ता भंडार पर गैस उपभोक्ताओं की भारी भीड़ लग रही है। लोग गैस सिलेंडर के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे है। हालांकि गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में काफी बदलाव हो गया है। अब बुकिंग सिलेंडर 45 दिनों में मिल सकेगा। फिलहाल जिला थोक उपभोक्ता भंडार पर घरेलु गैस सिलेंडरों की किल्लत देखने को मिल रही है। व्यवसायिक गैस सिलेंडर का वितरण तो पहले से ही बंद और अब घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी दिक्कतों का सामना आने वाले दिनों में भी करना पड़ सकता है। कारण यह कि सोमवार को गुजरात स्थित हजीरा गैस रिफिलिंग प्लांट पर काम बंद हो गया है। ऐसे में जिले से भेजी गई गाड़ियां लोड नहीं हो पाई है। जिला थोक उपभोक्ता भंडार में भी लगभग काम बंद वाली स्थिति हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार जब तक नया लोड नहीं आता तब तक वितरण नहीं हो सकेगा।

वर्तमान स्थिति में शहर में दो हजार से अधिक की वेटिंग हो चुकी है। जिले में यह आंकड़ा 7 हजार के पार पहुंच चुका है। सिलेंडर नहीं मिलने से आमजन खासा परेशान देखा जा रहा है। उपभोक्ता भंडार पर रोज भीड़ देखने को मिल रही है। गैस सिलेंडर लेने व बुकिंग को लेकर भंडार व आमजन के बीच कई बार बहस की स्थिति भी बनती देखी जा रही है। रविवार को 504 सिलेंडर का लोड आया था जो बांट दिया गया। अब गुजरात के हजारी प्लांट पर वितरण शुरू होने के बाद ही लोड आ पाएगा।

उधर देश की स्थिति को देखे तो केंद्र सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग जो 13 मार्च को 89 लाख थी वह 19 मार्च को 34 लाख घटकर 55 लाख प्रतिदिन पर आ गई है। घरेलु एलपीजी सप्लाई धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। वैष्णव के अुनसार अमेरिका-ईरान युद्ध के पहले से अगर तुलना करें तो वर्तमान में घरेलू एलपीजी का उत्पादन रिफाइनरी में 40 प्रतिशत तक बढ़ गया है। जमाखोरों और ब्लैक करने वालों पर सरकार सख्ती कर रही है। देश में 33 हजार रेड हुई है। इनमें 550 एफआईआर और 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार निगरानी के लिए 32 राज्यों में कंट्रोल रूम बनाए गए है। वैष्णव के अनुसार अभी कमर्शियल यूज में थोड़ी समस्या है, 20 प्रतिशत कमी है। कमर्शियल सिलेंडर की औसत डीमांड 4.5 से 5 लाख सिलेंडर की बनी हुई है।

केंद्र सरकार से जारी बयानों और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है यह तो नही कहा जा सकता है, लेकिन जिले में जो स्थिति गैस सिलेंडर को लेकर बन रही है वह तो यही दर्शाती है कि, गुजरात के हजीरा प्लांट से जब तक सप्लाय शुरू नहीं होती स्थिति बद से बदतर होने की संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर जिले में गैस की किल्लत साफ-साफ देखी जा रही है। जबकि अभी कुछ दस दिनों पहले तक जो स्थिति आज पेट्रोल-डीजल को लेकर बनी हुई है उसी तरह घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी थी। तब भी जिला प्रशासन व कलेक्टर ने लोगों से यही कहा था कि, जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में भंडारण भी है। अब महज दस दिनों के अंतराल में जिले में घरेलु गैस सिलेंडर की अपुर्ति लगभग ठप्प होने को है। सारा दारोमदार गुजरात के हजीरा प्लांट पर निर्भर करता है कि कब प्लांट चालू होगा, कब थोक उपभोक्ता भंडार की गाड़ी लोड होगी और कब झाबुआ पहुंचेगी और कब वितरण होगा। यहां भी संशय की स्थिति यह है कि, एक गाड़ी में औसत 500 गैस सिलेंडर ही आ पाएंगे। जबकि जिले में वेटिंग का आंकड़ा हजारों में है। कहीं ऐसा ना हो कि, पेट्रोल पंपों पर लगने वाली भीड़ की अफवाह हकीकत हो और आने वाले कुछ दिनों बाद जैसी स्थिति गैस सिलेंडर को लेकर बन रही है। वैसी ही स्थिति पेट्रोल-डीजल को लेकर आने वाले दिनों में बन जाए...? क्योंकि अधिकारियों का काम तो अपील करना है और वे अपना काम तो करेंगे ही...?

पहले घरेलु गैस सिलेंडर को लेकर भी प्रशासन ने अपील की थी कि, जिले में गैस सिलेंडर को लेकर कोई कमी नहीं है। अब पेट्रोल-डीजल को लेकर भी जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि, अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहों पर विराम लगाने के लिए प्रशासन की अपील खाफी हद तक सफल दिखाई दी है। जिला कलेक्टर, आपुर्ति विभाग से जारी अपील का असर लोगों में देखने को मिला है और बुधवार को जिला मुख्यालय के सभी पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य सी नजर आई है।

माही की गूंज भी आमजन से यही अपील करता है कि, अफवाहों पर ध्यान न दें जब तक किसी भी बात की पुष्टि या प्रमाण न मिल जाए तब तक खुद को शांत रखे। वरना आप भी अफवाह का हिस्सा बन सकते है। अफवाहों में आकर उत्तेजित ना हों, शांति बनाए रखें और पहले सूचना की पुष्टि जरूर करें।

मंडी में गेहूं की बंबर आवक, असुविधाओ के चलते ठगे जा रहे किसान, नहीं मिला समर्थन मूल्य

तोल काटे कि समस्याओं से जूझ रहा किसान, 50 किलोमीटर दूर तक से आने पर मजबूर

माही की गूंज, बामनिया/पेटलावद।

गेहूं की बंबर आवक के बाद किसानो को उम्मीद थी कि, वर्तमान की स्थितियो को देखते हुए सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2625 रुपए ओर उससे भी अधिक दाम पर उनकी उपज बिकेगी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी किसानों को सरकार से धोखा ही मिलता दिख रहा है। दूसरी ओर मंडी में किसान जो उपज लेकर आ रहा है असुविधाओ के बीच ठगा जा रहा है। पूरे क्षेत्र में सिर्फ बामनिया की मंडी में ही खरीदी हो रही है। जबकि करोड़ो की लागत से निर्मित पेटलावद सहित आसपास की दूसरी मंडिया सुनी पड़ी हुई है। एक ही मंडी चालू होने से बामनिया मंडी में सुबह 7 बजे से वाहनों की कतार लगना शुरू हो जाती है और 200 से ज्यादा छोटे-बड़े वाहन भर कर किसान अपना गेहूं लेकर मंडी पहुंच रहे है।

नहीं मिल रहा समर्थन मूल्य, सरकारी खरीदी 1 अप्रैल से

सरकार द्वारा किसानो से गेहूं की खरीद के लिए समर्थन मूल्य 2625 रुपए घोषित किया है और सोसाइटियों के माध्यम से गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन होना शुरू हो गए लेकिन खरीदी की प्रकिया एक अप्रैल से शुरू होना है। किसानो के पास अनाज भंडारण की व्यवस्था की कमी ओर पैसे की आवश्यकता के चलते किसान, सरकारी समर्थन मूल्य में गेहूं बिक्री के लिए इंतजार करने की बजाए मंडी में पहुंच कर माल बेच रहा है। सरकार का समर्थन मूल्य केवल सरकार की खरीद पर ही लागू है और मंडियों में किसानों का गेहूं 2100 से लेकर 2400 तक ही बिक पा रहा है।

मंडी में गेहूं लेकर आ रहै किसानो का कहना है कि, गेहूं खरीदी कम से कम समर्थन मूल्य तक बिकना चाहिए लेकिन व्यापारी गेहूं की बोली 2000 हजार से शुरू कर 2300 ओर उसके आसपास लेकर खत्म कर देते है। किसानो ने यहां तक कहा कि व्यापारी, मंडी में सिर्फ एक ट्राली गेहूं 2700-2800 तक खरीद कर मंडी में गेहूं ऊंचा बिकना बताते है। दूसरी ओर किसानो की गेहूं की फसल एक महीने से बिकना शुरू हो गई लेकिन समर्थन मुल्य पर खरीदी अभी भी शुरू नहीं हो पाई है जिससे किसानों को बाजार ओर मंडियों में माल बेचना पड़ रहा है।

कम भाव के बाद अतिरिक्त भी उठाना पड़ रहा नुकसान, तोल काटे कि व्यवस्था नहीं

गेहूं खरीद के बड़े व्यापारी और गोदामों की उपलब्धता के चलते कई बड़ी मंडियों की उपलब्धता के बाद भी बामनिया की कम सुविधा वाली मंडी का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा। जो कि विगत कई वर्षों से जारी है। बामनिया मंडी में गेहूं लेकर आ रहे किसानो को भाव तो कम मिल ही रहा है साथ ही अतिरिक्त नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। किसानो की उपज के तोल के लिए मंडी की ओर से तोल काटे तक की व्यवस्था नहीं होने से माल खरीद के बाद वजन के लिए बाजारों में जाना पड़ता है। जहां वाहनों को कतार में खड़े होकर खाली ओर भरे वाहन तोलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। साथ ही तोल काटे के पैसे भी किसानों को ही भुगतान पड़ता है। मंडी में मौजूद व्यापारी हर बार की तरह इस बार भी तोल काटे की व्यवस्था जल्द होने के दावे करते ही नजर आ रहे है।

बारदान के नाम पर काटा जा रहा है ,एक से डेढ़ किलो वजन

गेहूं नीलामी से लेकर भरा ओर खाली वाहन के तोल तक लाइन लगने के बाद जब किसान का गेहूं तुलता है तो व्यापारी प्रति क्विंटल एक से डेढ़ किलो गेहूं का पैसा काट लेता है।

मंडी में गेहूं लेकर आए किसान बाबूलाल बिलावल ने बताया कि, वजन होने के बाद व्यापारी बारदान के नाम पर किसान की उपज का 1 से डेढ़ किलो वजन काट रहा है जो सीधे-सीधे किसानो के साथ ठगी है। किसी किसान के द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो उसका प्रति क्विंटल आधा किलो गेहूं काटा जाता है। जबकि किसानो की उपज मंडी में तोली जाना चाहिए और ट्राली में खुला माल लेकर आ रहे किसानो से बारदान के नाम पर वसूली बंद होनी चाहिए। व्यापारी पूरी तरह से किसानो का शोषण कर रहा है जो माल उसे मंडी से उठाना है वो किसान के खर्च पर खुद गोदामों तक खाली करवा रहा है। उक्त लग रहे आरोप के बाद भी मंडी के जवाबदार इस प्रकार के मामले नकार रहे है।

30 से 40 किलोमीटर दूर से आने पर मजबूर

बामनिया मंडी में होने वाली गेहूं की आवक आसपास की नहीं बल्कि तीस से चालीस किलोमीटर दूर से किसान अपनी फसल यहां लेकर आने पर मजबूर है। बामनिया मंडी में रायपुरिया,जामली, अम्बापाडा,पीठडी,हमीरगढ़ सहित बनी,बोलासा क्षेत्र जो कि बामनिया से तीस से चालीस किलोमीटर दूर पड़ते हैं। जबकि रास्ते में रायपुरिया , पेटलावद जैसी बड़ी मंडी आती है लेकिन वहां मंडी प्रशासन ने किसानों की फसल खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसका खर्च भी किसानों को अतिरिक्त समय, वाहन भाडा खर्च कर बामनिया मंडी में आना पड़ रहा है। खुद को किसान हितैषी बताने वाली सरकार के राज में किसानों की दूर दशा देख कर किसानों के प्रति सरकार की मनोदशा का पता चलता है कि, आखिर किस प्रकार सिस्टम ओर व्यापारी मिल कर किसान को उसकी उपज का सही दाम नहीं दे रहे है।

राज की आत्महत्या का राज कुछ भी हो, दुख राज का नहीं परिवार व देश के भविष्य का

माही की गूंज, खवासा।

देश का युवा व किसान ये दोनों देश के भविष्य व विकास की रीड़ की हड्डी है। इसीलिए किसानों को अन्नदाता कहा जाता है वहीं शिक्षारत किशोर-युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। और यह दोनों देश के भविष्य की रीड़, आत्महत्या करने लगे तो यह दुख किसी परिवार का ही नहीं बल्कि देश का भी है और यह चिंतनीय है। किसानो की आत्महत्या के जब मामले आते हैं तो कारण उन पर कर्ज व आमदनी कम होने का सामने आता है और विपक्ष भी देश व प्रदेश की संसदों में अपनी आवाज किसानों के हक में उठाता है। सरकारे भी प्रयास करती है कि, किसान कर्ज तले न हो और किसानो की आय में भी बढ़ोत्तरी हो, विपक्ष व सरकार का यह नैतिक कार्य भी है कि किसानों के हक के लिए कार्य करें जिससे किसान आत्महत्याए न करें।

इसी तरह किसानों के चिंतन के साथ हमारा दायित्व है कि, देश का किशोर-युवा जो कि, देश का भविष्य है वे आत्महत्याए न करें। और जो आत्महत्याए हो रही है उस पर हम सब आत्म चिंतन करें तथा विपक्ष और सरकारे इस अहम मुद्दे व अनहोनी पर संसद में आवाज़ उठाकर समाधान के रास्ते निकाले।

आज का किशोर व युवा शैक्षणिक समय में ही भटकने लगा है और आत्महत्या को गले लगाने लगा है जो बड़ा व गंभीर विषय है...! उक्त आत्महत्याओ में एक मुख्य कारण कहीं न कहीं मोबाइल भी बन चुका है। वही क्लास में फेल होना, नंबर कम आना, शैक्षणिक समय में प्रेम-प्रसंग में धोखा, मोबाइल में ऑनलाइन ठगी व सट्टे बाजी आदि उक्त आत्महत्याओ के कारण बताए जाते रहे हैं। पर यह एक भी कारण ऐसा नहीं है जिससे हम हमारी जीवन लीलाएं ही समाप्त कर ले...?

यह सही है कि, जब भी इस तरह से देश के भविष्य किशोर-युवाओं की आत्महत्याओं के मामले सामने आते हैं तो पीड़ा मरने वाले व्यक्ति के प्रति किसी की भी नहीं दिखाई देती है ओर इसे गलत ही कहा जाता है। क्योंकि एक माता-पिता व परिवार हर परिस्थिति में अपने पुत्र-पुत्री के भविष्य के लिए सपने संजोता है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम कर इस उम्मीद के साथ पढाते-लिखाते है कि, पुत्र-पुत्री नाम रोशन करेंगें और उनके बुढ़ापे का सहारा भी बनेंगे। ऐसे में इस तरह की आत्महत्या, माता-पिता व परिवार के लिये दुखद तो है ही पर देश के लिए भी चिंतनीय है।

कुछ दिन पूर्व ही एक किशोर रतलाम निवासी ऋषभ भटेवरा की आत्महत्या का मामला सामने आया था। जिसमें ऋषभ ने अपने आईफोन से डाटा व अपनी सोशल मीडिया आईडी को हटा दिया और फिनाईल पाउडर पीकर आत्महत्या की। लेकिन आज तक आत्महत्या का कारण सामने नहीं आया पर आज भी उनके माता-पिता व परिवार के रो-रोकर उनकी आंखों में आंसू तक सूख गए हैं। इसी तरह एक इसके पूर्व पाटन के शिक्षित युवक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का छात्र था और चारे की दवाई पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया था। बताया जाता है कि, उक्त युवक की मौत के करिब एक माह बाद ही राजस्थान के शिक्षा विभाग से लेक्चरार पद का जोइनिंग लेटर मिला। ऐसे कई शिक्षारत विद्यार्थी व शिक्षित युवा छोटी-छोटी बातों को अपने दिमाग में बड़ा बनाकर आत्महत्या कर रहे हैं जो बहुत ही चिंतनिय हैं। इसी तरह खवासा में जैसे ही बुधवार को सूर्योदय के साथ लोग अपने घरों के बाहर निकले उसके पहले ही सोशल मीडिया पर सूचना मिली कि, किशोर राज चौहान की मौत हो गई। यह सूचना खवासा एवं क्षेत्रवासियों को भी विचलित कर गई और वही चिंता जाहिर करने लगे कि, आखिर राज चौहान की आत्महत्या का क्या कारण है...? कोई कहता है लड़की का मामला होगा...? कोई कहता है ऑनलाइन गेमिंग में हार गया होगा...? और कोई कहता है राज के पिता से कुछ कहा सुनी हो गई होगी...? इसलिए आत्महत्या कर ली होगी...!

बता दे कि, राज, कैलाश चौहान खवासा का इकलोता पुत्र था व तीन पुत्री है जिसमें से एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। राज एलएलबी का छात्र होकर रतलाम से अपनी पढ़ाई कर रहा था। साथ ही अपनी पढ़ाई के साथ वकालत की प्रैक्टिस भी पेटलावद न्यायालय में जाकर कर रहा था। राज के खवासा में गिने-चुने अजीज दोस्त जिसमें पवन कहार, उज्जवल चौहान, प्रभात (धोनी) लौहार, हिमांशु भटेवरा आदि थे। इन दोस्तों में सभी में बचपना होकर अभी किसी प्रकार की सामाजिक व पारिवारिक दायित्व की जिम्मेदारी नही है। वही इन दोस्तों में राज चौहान ही सबसे ज्यादा गंभीर, हसमुख मिजाज, सुलझा हुआ व परीपक्वता के साथ सबसे अच्छा व्यवहार व कम शब्दों में बात करने वाला था। ऐसे में राज की आत्महत्या के पीछे क्या राज है उसे जानना कोई नहीं चाहता है, बस यही आरोप कि राज ने यह जो किया वह गलत किया कह रहे है तथा माता-पिता व परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं।

वही माता-पिता व परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। बताया जा रहा है, तीन-चार दिन पूर्व राज ने चारे की दवाई पी ली थी और वह सो गया था। दोपहर में चाय बनने पर चाय पीने हेतु राज को उठने का बोला तो राज उठ गया और चाय भी पी। लेकिन चाय पीते ही उल्टी होने पर कीटनाशक दवाई की बदबू आने पर पिता व परिवार को संदेह हुआ और पूछने पर उसने चारे की कीटनाशक दवाई पीने की बात कही। जिसके बाद तत्काल स्थानीय उपचार के साथ बड़ौदा के एक बड़े निजी अस्पताल में ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान बुधवार को अल सुबह राज की मौत हो गई। जिसका अंतिम संस्कार स्थानीय मुक्तिधाम पर किया गया। राज की मौत के बाद परिवार के साथ उनके मित्र, परिवार, गांव एवं क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति शोक में है।

माही की गूंज हमारे देश के भविष्य किशोर-युवाओं से अपील करता है कि, हर समस्या के पीछे उसका समाधान भी है। ऐसे में हमारी समस्या को हम हमारे दोस्तों एवं परिवार के लोगों को अवश्य बताएं। किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या करना नहीं है। पुनः अपील करते हैं कि, किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या नहीं करे और अपने माता-पिता व परिवार की व्यथा व परेशानी को समझे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422